(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का छठा दिवस [संख्या 5

गुरुवार

दिनांक 7 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक प्रातः 9.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री विजयसिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि प्रतिवेदन के समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

प्रवर समिति के सदस्य की नियुक्ति

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति की सदस्यता से श्री मोहनलाल छंगाणी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने से रिक्त हुए स्थान पर श्री गुलाबसिंह शक्तावत राज्य मन्त्री गृह को नियुक्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी के इस्तीफा देने पर श्री गुलाबसिंह को नियुक्त करने का जो प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार किया जाय, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री केदारनाथ : मैंने समझा खेतसिंह जी नाश्ते की घोषणा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री गुलाबसिंह को सदस्य, प्रवर समिति नियुक्त करता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधयक, 1974

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री मोहनलाल छगाणी : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 3) सन् 1974 को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस सदन के समक्ष कुछ बातें रखी थीं और मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाने का पक्का इरादा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इरादा बड़ा नेक है कि पक्का इरादा रखते हैं, हमारा दृढ संकल्प है, हमारा पक्का इरादा है। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भूल हुई है। या तो अधिकारियों से गलती हुई या फिर प्रेस में गलत छप गया कि हम भ्रष्टाचार मिटाने का पक्का इरादा रखते हैं। मेरे खयाल से होना तो यह चाहिए था कि हम भ्रष्टाचार बढाने का पक्का इरादा रखते है, शायद यही भाषा है लेकिन गलत छप गई है।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार अब मिट नहीं सकता है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह बीमारी है जिसका इलाज मौजूदा सरकार के पास नहीं है। यह तो स्वयं भ्रष्टाचार चाहती है तो फिर भ्रष्टाचार किस प्रकार से मिट सकता है, किस प्रकार से समाप्त हो सकता है? यह तो ऐसा रोग है जो अंग अंग में व्याप्त हो चुका है जिसका इलाज आपके पास नजर नही आता है। केवल यह कह देने से कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। किसी भी तरह से मिटने वाला नहीं है क्योंकि आज हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया है, देश का चरित्र इस प्रकार का हो गया है कि वास्तव में भ्रष्टाचार तो अपने रोजमर्रा के काम का अंग बन गया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार मिटाना चाहें, लोक आयुक्त बैठा कर और

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
ऐसे कानून बना कर, प्रिवेंसेज रिमूवल कमेटी से तो भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे जन नेता हों या राज नेता हों, व्यापारी हों या मजदूर हों, आज सब करप्ट हैं। हो सकता है कि हजार में से दो चार लोग करप्ट नहीं हों लेकिन अधिकांश लोग करप्ट हैं, अधिकतर संख्या में करप्ट हैं तो भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अब तो ऐसा कर दिया जाय कि फीस की तरह से पैसा बांध दिया जाय। आज यह हाल है कि लोग नौकरी भी किस प्रकार की चाहते हैं, मेरे पास भी लोग नौकरी के लिए आते हैं तो चाहेंगे कि उनको ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर बना दिया जाय, उनको थानेदार बना दिया जाय, उनको एक्साइज अफसर बना दिया जाय, सेल्स टैक्स अफसर बना दिया जाय। क्यों नहीं वे सेटलमेंट में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं शिक्षा विभाग में जाकर अध्यापक बनना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि इन विभागों में ऊपर की कमाई है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : What is your Point of order.

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जो भी माननीय सदस्य हैं उनके लिए योग्यता निर्धारित है, उनके उपरान्त भी जो कल महामूर्ख बन कर महामूर्ख सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं तो वे अपनी योग्यता खो चुके हैं। उनको अब इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वाट इज यूवर पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री दीपंकर : क्या महामूर्ख भी इस सदन में भाग ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : What is your point of order. I couldnot understand, order please.

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : आप रिश्वत का एक स्टेण्डर्ड बना दें कि थानेदार फलां काम के लिए इतना ले सकेगा, सेल्स टैक्स वाला इतना ले सकेगा और दूसरे विभाग वाले इतना ले सकते हैं। रिश्वत की रेट बांध दें रिश्वत का भत्ता बांध दें तो भ्रष्टाचार नाम से नहीं रहेगा लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

इसके बाद में आता हूं पंचायतों के मामले में। इस बारे में हमारे प्रदेश को सबसे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था कि हमने सारे देश में सबसे पहले अपने यहां पंचायत संस्थाओं की शुरुआत की। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर इनकी हालत क्या है? दुख की बात तो यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसकी कहीं चर्चा तक नहीं है कि पंचायतों के चुनाव कब करवाये जायेंगे। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत चुनावों को पुनः टाल दिया गया है। आखिर आप क्या चाहते हैं? इन पंचायत के चुनाव नहीं कराकर पंचायत के जन प्रतिनिधियों की दशाब्दी मनाना चाहते हैं, और उससे भी आगे जाकर क्या रजत जयन्ति मनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर आपका इरादा क्या है? दूसरी पंचायतों की हालत इतनी खराब

(सुरेशचन्द्र शर्मा)
हो गई है कि न उसमें काम करने का उत्साह है, न उनके पास कोई काम है। सरपंच और प्रधान में कोई जोश नहीं है। आपस में मतभेद बढ़ गये हैं, काम होता नहीं है, इसलिये आप या तो इनको समाप्त कीजिये और फिर या आप इनके चुनाव कराइये।

जिस हालत में आप इनको चला रहे हैं उससे कोई काम नहीं हो रहा है। न तो उनके पास पैसा है, न उनको आपने कोई काम दे रखा है सिवाय अध्यापकों की तनख्वाह बांटने के कोई काम नहीं रह गया है। सदन में यहां बराबर घोषणायें की जाती है कि इनके काम में सुधार लायेंगे लेकिन आज तक आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं अब समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा : आखिरी बात कह कर समाप्त कर देता हूं अध्यक्ष महोदय राजस्थान हाईकोर्ट की बाबत इस सदन में बराबर चर्चा होती रही है और लोकतन्त्र में विश्वास करने की हम बराबर घोषणा करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन के 117 माननीय सदस्यों ने राजस्थान हाई कोर्ट को बेंच जयपुर में स्थापित करने के लिए····

श्री दीपंकर : हाई कोर्ट के मामले को वकील होने के नाते उठाना चाहते हो ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्या फरमा रहे हैं ?

श्री दीपंकर एवं श्री सुरेशचन्द्र शर्मा लगातार एक साथ बोलते रहे–

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री दीपंकर : जनता को आप किसी तरह से गुमराह करना चाहते हैं, यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं है। हाई कोर्ट की बेंच यहां आने वाली नहीं है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : हाईकोर्ट के यहां आने से आपको ज्यादा पैसा मिल सके, आपका पेशा समाज में सबसे ज्यादा भेदभाव पैदा करने का है। आप लोगों को करप्ट करना चाहते हैं और समाज की दुहाई देते हैं, उनकी वकालत करना चाहते हैं। जनता को चक्कर में डालना चाहते हैं····

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : इस सदन में आधे से ज्यादा वकील होंगे, उनके लिए इस प्रकार से कीचड़ उछालना अच्छा नहीं है····

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : आपका आदेश अलग रहा, वह तो स्वयं परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे बहुत तकलीफ है माननीय सदस्य से। मैं तीन रोज से बराबर

Page No 5

5

(श्री अध्यक्ष)

देख रहा हूं कि बराबर आसन की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। घण्टी की परवाह नहीं करते हैं। कोई कुछ कहते हैं तो उसको सुनना नहीं चाहते हैं और जान बूझ कर बीच बीच में इण्ट्रप्ट करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है और आगे से इस बात को दोहराया नहीं जाना चाहिये। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उनकी बात आपको नापसन्द है तो आपको भी मौका मिलेगा उस समय आप भी कह सकेंगे। हाई कोर्ट का लफ्ज आया और उठ खड़े हो गए····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह फोबिया हो गया है।

श्री अध्यक्ष : अब इस तरह से कोई भी बोलता हो उसके बीच में खड़े हो जायेंगे। तो किस तरह से अनुशासन रह सकेगा, किस तरह से कार्यवाही चल सकेगी। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आप करेंगे तो जब आप बोलेंगे आपको भी रोक सकते हैं। मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी कुछ कह रहा हूं, तब भी शांत नहीं हो रहे हैं, बीच में ही कुछ कहना चाह रहे हैं। यह संसद की, सदन की मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ आपको कहना हो उसके लिए आप समय ले लें और फिर जितना कहना चाहें कहें। लेकिन इस तरह से ढोली का मूड यहां पर नहीं चल सकेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करूंगा लेकिन हमारे पक्ष को भी समय मिलना चाहिए। अभी तक किसी विषय पर समय नहीं दिया गया है तो हमें भी समय दीजिए, हमें भी बोलने दीजिए। हम भी राजस्थान के हित में कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह की बातों से राजस्थान का विघटन नहीं हो। पटेल साहब ने बड़ी मुश्किल से राजस्थान को मिला कर निर्माण किया है···

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं, लेकिन समय लेकर बोलें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आप समय दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष : जब आपका नम्बर आएगा तो आपको भी समय मिलेगा लेकिन एक माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं और उसमें क्योंकि हाई कोर्ट का नाम आया और आप खड़े हो गए तो दूसरे कैसे बोलेंगे, कैसे कार्यवाही आगे चलेगी? इसलिए समय लेकर बोल लीजिए।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा ख्याल है कि माननीय सचेतक महोदय वही प्रस्ताव अब रखना चाहते हैं जो उन्होंने माननीय गिरधारीलाल भार्गव के लिए यहां रखा था। पहले उनके प्रस्ताव को सुन लिया जाय।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि हाई कोर्ट की बैंच के लिए जो जनता की मांग है···

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अभी समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन कर रहा था कि इसी सदन के 117 माननीय सदस्यों ने राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित करने के लिए लिख कर दिया था लेकिन राजनैतिक कारणों के आधार पर इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण से इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कितने मुख्य मंत्री इस बीच में बदल गए हैं। तीन-तीन मुख्य मंत्री बदले हैं और अब तो जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो वर्तमान में लॉ मिनिस्टर हैं, जो कानून मंत्री हैं इस समय···

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत क्यों जाते हैं।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : वे इस प्रश्न पर विचार कराने से सकपकाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जनता की मांग है, जो सदन के अधिकांश सदस्यों की मांग है, बहुमत की मांग है, राजस्थान के न्याय का सवाल है उसके आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच का मसला हल होना चाहिए और बैंच कायम होनी चाहिए। पिछले सत्र में भी घोषणा की गई थी कि यह सवाल अभी तक खुला हुआ है, अन्तिम रूप से फैसला नहीं हुआ है तो जब यह सवाल खुला है, विभिन्न प्रदेशों में जगह जगह पर बैंचें हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो राजस्थान में भी बैंच कायम होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी घण्टी का आदर करते हुए यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो यहां पधार कर सदन को सम्बोधित किया, मैं उसका स्वागत करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव उनके प्रति पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज सवाल राजस्थान को एक रखते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का है। विरोधी पक्ष के नेताओं और कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सरकार के पास सिवाय झूंठ बोलने के कुछ भी नहीं है। उन्होंने सरकार के कार्यक्रम को देखने की कोशिश ही नहीं की है। उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को केवल एक लेखा मात्र माना है, परन्तु राजस्थान में जो योजनाएं बनी हैं उन्हें देखने का उन्होंने कष्ट नहीं किया है। आज राजस्थान के बारे में जो योजनाएं बनी हैं, उनको अगर सही दिशा में देखें तो उनसे राजस्थान की काया पलट हो सकती है। यह राजस्थान एक ऐसा इलाका था जहां पीने का पानी नहीं मिलता था, जहां सिंचाई नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन आज जगह जगह बांध बनाये गये हैं और कई बड़े-बड़े कदम उठाये गये हैं।

मैं समाज कल्याण के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। आज जितना पैसा समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च किया जा रहा है अगर वह पैसा एक योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाये तो उससे

(श्री दीपंकर)

बहुत कुछ फायदा हो सकता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, उस तरह सरकार भी अगर इस समाज कल्याण विभाग का खर्चा करे तो उससे यह मसला पूरा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस दिशा में सोचेगी।

जहां तक स्कूलों का सवाल है, सरकार ने मिडिल स्कूल और प्राईमरी स्कूल काफी खोले हैं, लेकिन मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज कई ऐसी एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, ऐसी शिक्षण संस्थायें हैं जहां साम्प्रदायिकता फैलाने का षडयन्त्र किया जाता है। उन स्कूलों में ऐसा षडयन्त्र चल रहा है कि जिससे डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाये और लोग एक दूसरे से लड़ने लग जायें। इस तरह का वातावरण उन स्कूलों में फैलाया जाता है। शिक्षा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि यह भगवा झंडा जो एडेड स्कूलों में फहराया जाता है, वह फहराया जाना बन्द हो जाय।

जहां तक सस्ता न्याय दिलाने का सवाल है, हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। उनको सस्ता न्याय किस प्रकार से मिल सकता है इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। राजस्थान में न्याय पंचायतों की स्थापना होने के बाद उनको कुछ सस्ता न्याय मिलता था लेकिन आज सरकार उन न्याय पंचायतों को खत्म करने के बारे में सोच रही है। तो इससे जो सस्ता न्याय दिलाने की एक प्रणाली चालू की गई थी, वह भी रुक जायेगी। इसलिये सरकार को इस पर सोचना चाहिये।

आज चाहे एस. डी.एम. की कोर्ट हो चाहे और कोई भी कोर्ट हो, वहां पर समाज का एक भ्रष्ट तबका हावी है। वह भ्रष्ट तबका है वकील तबका। अगर हिन्दुस्तान की गरीब जनता को बचाना है तो इस वकील समाज की जितनी भी डिग्रीज हैं, वह कैन्सिल कर देनी चाहिए। गरीब आदमी को किसी वकील की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे वकीलों की आवश्यकता नहीं है जो सर्विस क्लास वालों की दलाली करें। जो समाज को भ्रष्ट करें और जनता को न्याय दिलाने के नाम से धोखा दें, हमें ऐसे वकील तबके की जरूरत नहीं है।

बहुत अर्से से यह मांग चली आ रही है कि हाईकोर्ट की एक बैन्च जयपुर में होनी चाहिये और हाईकोर्ट की बैंच न होने से पूर्वी राजस्थान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह की बात कह कर हाईकोर्ट की बैंच मांगी जा रही है। वास्तव में देखा जाय तो यह जनता के साथ मखौल है, यह प्रजातन्त्र के साथ मखौल है और जिन लोगों ने राजस्थान का एकीकरण किया, जिन लोगों ने राजस्थान की अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक किया, उन लोगों के साथ मखौल है। जिस तरह से वह एकीकरण हुआ, जिस तरह से पटेल साहब ने राजाओं को समझाया और समझाकर एकीकरण किया, वह बेकग्राऊन्ड भूलना नहीं चाहिये। उस समय यह

(श्री दीपंकर)

सवाल था। आपका अभी समय लेकर हाउस का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। यदि पटेल की हस्ती नहीं होती तो यह एकीकरण ही नहीं हुआ होता। जो लोग एकीकरण पर विश्वास नहीं करते थे वे चाहते थे चाहे पाकिस्तान में मिलें, चाहे भारत में मिलें और चाहे अलग से कोई राज्य बने जो स्वतन्त्रता के नाम पर इसका दुरुपयोग करना चाहते, उनको नहीं करने दिया और पूर्ण एकीकरण कर भारत का स्वरूप बनाया। किस तरह की उन्होंने पैरवी की और किस तरह बड़े बड़े शहरों को खुश रखा और उस समय ही यह तय किया गया था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में रख दी जाय, हाई कोर्ट की बेन्च जोधपुर में रख दी जाय, राजस्व मण्डल, अजमेर में रख दिया जाय, एज्यूकेशन का कार्यालय बीकानेर में रख दिया जाय इसलिए हमारा इतिहास इसका साक्षी है। अब जयपुर के महत्व को कम कैसे कर सकते हैं, जोधपुर के महत्व को कम कैसे किया जा सकता है उसी प्रकार अजमेर और बीकानेर के महत्व को भी कम कैसे किया जा सकता है? उनके महत्व बनाये रखने की दृष्टि से हाई कोर्ट, जोधपुर में रखना तय किया था। हाई कोर्ट जोधपुर में रहता है तो पूर्वी राजस्थान को क्या शिकायत हो सकती है, हमारी समझ में नहीं आता है। बड़ी अदालतों का सम्बन्ध गरीबों से नहीं होता है। उसका लाभ तो कुछ व्यक्ति ही उठाते हैं और उस लाभ को उठाने वाले की क्षमता भी होती है कि वह जोधपुर में जाकर लड़े। आज जोधपुर में कितने ही वकील जाकर सेटिल हो गये हैं। जो कहीं वकालत नहीं करना चाहते हैं केवल चेम्बर प्रेक्टिस करना चाहते हैं और केवल नाम मात्र को हाई कोर्ट में आते हैं उनका भी यह मानना है कि हाई कोर्ट की बेन्च यहां आये। न गरीब आदमी का हाई कोर्ट से सम्बन्ध है और न सुप्रीम कोर्ट से गरीब आदमी का सम्बन्ध है। अगर इसी प्रकार की मांग है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी हर राजधानी में होनी चाहिये, उसे भी कर दीजिये लेकिन सम्भव नहीं है तो उसी प्रकार हाई कोर्ट के लिए भी अब सम्भव नहीं है। हाई कोर्ट एक स्टेट में होगा, एक जगह होगा उस हिसाब से इसे जोधपुर में रखा गया है। यदि हाई कोर्ट की बेन्च यहां आती है तो अलग से लायब्रेरी रखना होगा, अलग से स्टाफ रखना होगा, अलग से इसकी बिल्डिंग बनानी होगी, अलग से सारी व्यवस्था करनी होगी और अलग से जजेज के लिये रहने की व्यवस्था करनी होगी और इससे राजस्थान की कई योजनायें अधूरी रह जायगीं। महज केवल चन्द वकीलों के कहने से हाई कोर्ट का नाम लाया जाय और उसके लिये लाखों रुपये बरबाद किये जांय। महज कुछ लोगों ने बैठकर तय कर लिया और प्रसार कर दिया और अब वह बात छूटती नहीं है। एक तरह से वह बात अभी चुभी हुई है। हाई कोर्ट लाने से उनका भला हो जायगा, यह समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां जिस तरह का महत्व बढ़ा हुआ है, वह अवश्य कम हो जायेगा, लेकिन न्याय मिल जायेगा, इसमें शंका है। इसमें राजनैतिक कारण हैं, वकीलों का स्वार्थ है, चन्द लोग बहकाये हुये हैं।

(श्री दीपंकर)

अगर हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर में लाई गई तो मैं साफ निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान दो टुकड़ों में विभाजित हो जायगा। वह दिन राजस्थान के इतिहास में नहीं आये, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों एक छोटा सा मसला आया था कि एक नई युनिवर्सिटी कहां खोली जाय तो अजमेर से आवाज उठी, बीकानेर से आवाज उठी इसलिये जोधपुर के लोगों में विचार नहीं आयेगा कि उनके महत्व को घटाया जा रहा है। हम राजस्थान के विकास की ओर न सोचें, राजस्थान के अकाल की ओर नहीं सोचें, हम राजस्थान की खुशहाली की ओर नहीं सोचें, हम राजस्थान की बाढ़ की स्थिति की ओर न सोचें और महज यह बात सोचें कि किस तरह हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में आये··

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे पूरा विश्वास है माननीय सदस्य हाई कोर्ट की बेन्च लाने में कोई तथ्य नहीं समझेंगे। जिस कमीशन ने कहा, हो सकता है, किसी कमीशन ने कह दिया, राजस्थान ने किसी कमीशन को नहीं बनाया। इस कांग्रेस के महान नेता पं. जवाहरलालजी के पीछे सरदार पटेल साहब थे और पटेल साहब यह जानते थे कि राजस्थान में जयपुर और उदयपुर की बात हो गई थी। एक साथ में खाना खाने नहीं बैठते थे। ये छोटी छोटी बातों पर आन बान करने वाले लोग थे इसलिए उनके दिमाग में यह आया कि एक एक महकमा सबको दो। आज पटेल साहब को भूल जायं, उनकी भावना को भूल जायं और एकीकरण की जो भावना है, उससे विपरीत चले जायं यह कोई माननीय सदस्य नहीं सोचेगा और महज वकीलों का बहकावा है बाकी हाई कोर्ट की बेंच आने से कोई भला होने वाला नहीं है। एस. डी. एम. कोर्ट में, मुन्सिफ कोर्ट में जो भ्रष्टाचार है उनको सरकार पकड़े। यह जो खोटा धन्धा करते हैं, देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनको पकड़ो, यह बहुत बड़ा काम होगा। इस राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल होगा अन्यथा हम आपस में लड़ पड़े और राजनैतिक आधार पर विभाजन कर दें तो मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास का वह काला दिन होगा, बुरा दिन होगा। हम इस देश में तुच्छ भावना वाले कहलायेंगे। यहां सेक्रेटेरियट है तो अच्छा प्रकाश दीजिये, राजस्थान को अच्छा निर्देश दीजिये, राजस्थान के लिये अच्छा बजट तैयार कीजिये···

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : मैं समझता हूं तुच्छ मांग को आप लोग नहीं उठायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अब मुख्य मंत्री जी का भाषण हो जाए तो अच्छा है।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक जो अपना अभिभाषण सदन में दिया और जिसके ऊपर श्री गोटेवाला साहब ने धन्यवाद के लिए प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री लूणाराम)

आज मंहगाई, बेरोजगारी और सरकारी कार्यालयों में लालफीताशाही व भ्रष्टाचारी, सभी कारणों से हर जनजीवन अपने आप में मायूस और निराशापन महसूस कर रहा है। आज इस समय के अन्दर जब हम रह रहे हैं तो चहुं ओर मंहगाई ही मंहगाई का जिक्र सामने आता है और बहुत वाजिब भी है आना क्योंकि यह जन जीवन से सीधा संबंध रखने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, यह मंहगाई आज ही उत्पन्न हुई हो यह बात नहीं है। यह तो केन्सर की बीमारी थी और उस समय से थी जिस समय से कि दो नम्बर के पैसे का व बही खातों का चलन शुरू हुआ। उस समय से यह स्थिति इस देश के अन्दर शुरू हुई और आज उसने अपना उग्र रूप इस कदर धारण कर लिया है कि जिससे हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यह सारी कार्यवाही किस के द्वारा हुई, किस के द्वारा की गयी यह भी चन्द लोगों की शरारत है और आज वही लोग इसके लिए सरकार से अपनी स्वार्थ सिद्धि अभी व बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों में इस चीज की ऊबड़ खाबड़ ज्यादा हो रही है। अध्यक्ष महोदय इस मंहगाई को पैदा करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति और उनके मुनीम हैं, बड़े बड़े आफिसर्स हैं और आज महगाई के युग का पालने का श्रेय उनको हैं और उनके द्वारा पैदा की गया मंहगाई आज इस कदर सामने आई है और आज भी इसके लिए तोड़ फोड़ वही लोग कर रहे हैं और इसलिए कर रहे है कि बड़े आफिसर ने बंगला बनाया तो पास में बैठने वाले के भी मन में बंगला बनाने की इच्छा हो गयी और इस सारी की सारी मंहगाई के युग में पूर्ति नहीं होती है। तो सभी चीजों की लड़ाई उनमें बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने की होती है। यही हाल आज सेठों का है और सेठों से मुनीम आगे बढ़ रहे हैं और यह काम करने वाले और काम चोरों की लड़ाई है। इसके अन्दर चाहे किसी को भी बुराई दी जाये या कोई भी राजनैतिक दल इसमें सहयोग दे तो यह उनके लिए बेकार है। क्योंकि पूंजीपति वर्ग व अधिकारी वर्ग दोनों ही ऊंचे पड़ते हैं। इसीलिए जनता आज भी इस मंहगाई से परेशान होते हुए भी इस की लड़ाई को अपने धैर्य के साथ देख रही है और वह कुछ भी चीं चपट नहीं कर रही है, क्योंकि वह परेशान जरूर है। आज का गरीब मजदूर, गरीब किसान अपने आप में चुपचाप धैर्य के साथ यह सब कुछ तमाशबीन की तरह देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब तक इस मंहगाई के लिए हम उपाय नहीं सोचेंगे और मंहगाई मंहगाई करते रहेंगे तब तक इस मामले के अन्दर कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसके लिए जब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये जायेंगे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कारगर कदम उठाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आज जो समाज के अन्दर असमानता बढ़ रही है, एक तरफ तो एक हवेली आकाश को छू रही है और दूसरी तरफ आज गरीब और मेहनतकश लोग धोड़े में बैठे हैं और छाया के लिए वृक्ष तक नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, यह सारी असमानतायें हैं। एक तरफ कपड़ों के बाग बगीचे और एक तरफ किसान के पास एक इंच जमीन

(श्री बूणाराम)

तक नहीं है जो मेहनत करता है यह सारी चीजें अपने आप में असमानतायें पैदा करती हैं प्रतिशोध पैदा करती है और इस ऐशो-आराम को देखकर हर आदमी की जिज्ञासा एवं महत्वाकांक्षाए बढ़ती हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं अपने आप में कमजोर रहूं, अच्छा मकान न रखूं, अच्छे कपड़े न पहनूं, अच्छा बंगला, कार तथा बगीचा न रखूं यह सारी चीजें देखा-देखी बढ़ रही हैं और इसको जब तक आप कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक यह मंहगाई हरगिज रुकने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि इन चीजों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। आज उदाहरण के लिए अधिक मकानों की किसको आवश्यकता है। एक गरीब को, क्योंकि उसके बाल-बच्चे अधिक होते हैं और मकान होते नहीं, दूसरी तरफ पूंजीपति लम्बे चौड़े मकान की रखवाली के लिए नौकर रखता है क्योंकि उसके कई मकान होते हैं वह किस-किस में रहे और किराया किसी को देता नहीं। एक पूंजीपति मकान बनाता है और उसी मकान पर वह एक नम्बर का पैसा 1 लाख खर्च करता है तो कम से कम 5 लाख रु. दो नम्बर का उस पर खर्च करता है और अपने कागजों में और खाते में उसको एक लाख का दिखाता है जब कि बिल्डिंग 6 लाख की बनती है। अगर यह असत्य बात है तो सरकार को चाहिए कि जिनके पास कोई मकान नहीं है और सरकार उनको मकान हाउसिंग बोर्ड के जरिये बनाकर दे रही है अच्छा हो कि पूंजीपति लोगों ने जिस प्रकार से मकान बना रखे हैं और इन्कम टैक्स से बचने के लिए खातों में एक लाख रुपया मकान लागत का दिखा रखा है उनको ड्योढा पैसा दे दिये जाय और उन मकानों को आवासहीन लोगों में अलाट कर दिये जाने चाहिए जो कई परिवारों को काफी होंगे, तब जाकर इन पूंजीपतियों को मालूम होगा कि अब हमारे ऊपर मुसीबत आई है। यह दो नम्बर के पैसे से खुद ही अपनी मौत बुलाई जा रही है। सरकार कोई पैसा खर्च करने में कमी नहीं रख रही है और उसका नतीजा मेहनतकश लोगों को उलटा भुगतना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब तक हम गगन चुंबी अट्टालिकाओं बाग-बगीचों, कारों और विवाहों की फिजूलखर्ची को और जिससे समाज में भेद-भाव पैदा करने वाले अन्य कार्य हैं उनको नहीं मिटा पायेंगे उनके ऊपर कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे तब तक मंहगाई के ऊपर कन्ट्रोल होना मुश्किल है। और इन पर पाबंदी लगने से दो नम्बर के पैसे खर्च करने का आकर्षण नहीं रहेगा इसलिए दो नम्बर की कमाई जोड़ना भी कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो दूसरी बात है वह यह है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं–आज एक किसान सौ रुपया तकावी के लिए कर्ज लेता है तो उसकी एक साथ वसूली की जाती है और कोई जमाना या अकाल का सवाल नहीं है और आज कारखाने के मालिक को लाइसेन्स देकर लाखों रुपया कर्ज के रूप में सरकार दे देती है और लाखों का सस्ती दर पर सामान दिया जाता है और वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यह कार्य मेरे को नहीं करना है और कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अधिक से अधिक

Page No 12

(12)

(श्री लूणाराम)

सरकार को लम्बे समय में रकम चुका देंगे और मामूली ब्याज लगेगा। तो वह उसमे कमी रखते हुए पूंजी तो अपने दूसरे कामों में लाकर हमारे अन्दर और गरीबी पैदा कर रहे हैं और वह करोड़पति और लखपति बनते जा रहे हैं और उनको सस्ते ब्याज को वजह से उस पैसे की चिन्ता नहीं है। आज पांच रुपया सैंकड़ा के हिसाब से मजदूर और किसान को पैसा कर्ज नहीं मिलता है और ऐसे पूंजीपति और कारखाने वालों को 8 आना और दस आना के हिसाब से किसान व मजदूर की पसीने की गाढ़ी कमाई टैक्स द्वारा इकट्ठी हुई को सरकार से पैसा मिल रहा है। आज उनके ऊपर करोड़ों और लाखों रुपया बकाया है जिसकी वसूली को सरकार को चिन्ता नहीं है और दूसरी तरफ गरीब किसानों के साथ यह चीज हो रही है कि उनकी धरोहर छोटी चीज भी कुर्क की जा रही है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

थोड़े से ही समय में निवेदन कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज इसी प्रकार से हमारे पश्चिम राजस्थान के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है जो कि पैदावार के अन्दर बहुत कमजोर है और खरीफ की फसल के लिए जो बरसात होती है सिर्फ चार महीनें ही किसान और मजदूरों को काम मिलता है, वह भी अगर जमाना अच्छा हो तो, बाकी आठ महीने के समय में ऐसे लोग जो छोटे किसान हैं या मजदूर हैं सारा का सारा समय बेकार रहते हैं और जब भी कभी अकाल होता है या दैवी प्रकोप होता है तो सरकार उनको कोई मदद नहीं देती स्थायी साधन के लिये और न उनको मरने देती है और न जिन्दा रहने के लिए जमाना होने पर कुछ छोड़ती है और सरकार उनको कोई स्थायी व्यवसाय का कोई काम नहीं दे रही है। किसान की पांच-छः साल से रकम माल-गुजारी मेरे क्षेत्र में बकाया पड़ी है। चालू साल का लगान के साथ एक साल का बकाया लगान आप और ले सकते हैं इस प्रकार का नियम है। पर वहां तीन साल का वसूल कर लिया गया है। और शेष बकाया मांग रहे हैं, यह अन्यथा हो रहा है अधिकारियों की तानाशाही के कारण इसकी आप रोकथाम करें।

इसी तरह लेवी का प्रश्न है। इसका विरोधी पार्टी विरोध भी करते हैं और हम देने के लिये भी कह रहे हैं। जो देने की बात हम गांवों में करते हैं उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इसमें कुछ दोष हमारा भी है। हम लेवी क्यों दें? और किसको दें? किसके लिये दें।

अध्यक्ष महोदय, आज लेवी देने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास अनाज नहीं है, जो राशन लेने में असमर्थ हैं, उनको सस्ती रेट पर देकर उनकी सहायता पहुँचाई जावे। पर आज लेवी में लिये हुए इस अनाज को पैसे वालों को, करोड़पतियों को शहरों में दिया जा रहा है। यह क्यों? वे तो दस गुना मंहगे भाव पर भी खरीद कर ले सकते हैं। पर आप उनको देते हैं और गरीब वंचित रहता है। तो यह भी सोचना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इन्कम टैक्स सेल्स टैक्स देता है उसको इस सस्ते अनाज आदि से वंचित रखना

(श्री लूणाराम)

चाहिये उसे सस्ती रेट पर कोई अनाज सरकार नहीं दे। और जो इन्कम टैक्स देने वाले नहीं हैं, उन लोगों को आप सस्ती रेट पर चाहे शहर में रहने वाले हों या गांवों में, दें। और यह भी तय करें कि जिनके पास अनाज है ही नहीं इस साल भरण-पोषण लायक है। उनसे लेवी न लें। दूसरी तरफ ऐसे भी पैसे वाले बड़े-बड़े जमीनदार किसान और पैसे वाले करोड़पति लखपति लोग हैं जो सस्ते भाव पर राशन का अनाज खरीद कर उसे स्वयं नहीं खाते, अपने जानवरों को खिलाते हैं। पशुओं को दे देते हैं मेरे इलाके में कणक नहीं पैदा होता, वार–त्योहार बहुत आवश्यकता होती है, वैसे बाजरे का हमारा इलाका है। पर वार त्योहार हम लोगों को आप कणक दिलवा दें, पर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं यह बहुत बड़ी भेद-भाव वाली बात है। हमें तो होली के मौके पर ही कणक दिलवा दें।

श्री केदारनाथ : होली तो आई आज। अब माथुर साहब क्या पहुँचावेंगे। माथुर साहब, आपको भले ही दे दें, उनसे लेकर चले जावें आप।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अगले साल का 75 का विश्वास ही दिला दें।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : मैंने यह नहीं कहा कि गांवों में नहीं बांटा जावे। हमारे पास जो है जिले के हिस्से के माफिक बांट देने की बात मैंने कही है। अब वह शहर में बांटा जाता है या गांव में यह जिला अधिकारी की बात है।

श्री लूणाराम : उनको तो आप जैसा आदेश देंगे वे तो वैसा ही करेंगे। गांवों में नहीं बांटते हैं। यह साफ मैं बता दूं कि गांवों में अनाज नहीं बांटा जा रहा है। सभी शहरों में बांटा जा रहा है। गांवों में आज ज्वार बाजरा दिया जा रहा है कणक का प्रश्न नहीं। तो यह बात हुई लेवी के बारे में व राशन वितरण प्रणाली के बारे में।

सैद्धांतिक रूप से मैं लेवी के विरोध में नहीं हूं। पर जिस ढंग से यह ली जाती है उसमें मुझे भी ऐतराज है। मेरे क्षेत्र में 135 रुपया प्रति क्विटल का भाव है। तो इन भावों को ध्यान में रखकर सरकार को भाव बढ़ाने चाहिए और जिनके पास उत्पादन हुआ हो उन्हीं से ली जानी चाहिये। इसके लिये प्रचार भी आपको काफी ठीक तरह से गांवों में करना चाहिये। अगर इस तरह से आप अपनी नीति बनावेंगे तो लेवी की अच्छी वसूली हो सकती है।

शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूंगा। स्कूलों में अधिक से अधिक प्राईमरी स्कूलें, अपर प्राईमरी स्कूलें खोली जावें। सेकण्डरी स्कूलें पहले जो खोली गई उनमें कामर्स और साइन्स के विषय नहीं हैं। ये उसमें चालू किये जावें। इसके बिना गांवों में असन्तोष और बढ़ेगा ताकि बिना तकनीकी शिक्षा के बच्चे का आकर्षण रहे। गांवों में भी वहां के लोगों की रुचि के अनुसार विषय खोले जावें ताकि उसका पूरा लाभ वे ले सकें।

इसी तरह से यातायात के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा। 25 प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण करके आपने अच्छा काम किया।

(श्री लूणाराम)

पर इसके साथ-साथ जो परिवहन के कार्य–कर्ता और अधिकारी सभी की लापरवाही से बहुत अधिक भ्रष्टाचारी धांधलीबाजी बरतते हैं उनको रोका जावे। आपने यह कोई फैमीन तो उन लोगों के लिये खोला नहीं है जनता को यातायात की राहत देने के लिये खोला है तो जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई जो ठीक तरह से राज्य के खजाने में आनी चाहिये वह उनकी लापरवाही के कारण आधी भी नहीं आ पाती इसको सर–कार को रोकना चाहिये। बीकानेर से 1।। बजे एक्सप्रेस चलती है। इसका बीच में पांच जगह स्टापेज है। पर इसमें इतने आदमी भरे गये 1 मार्च 74 को रतनगढ़ से कि खड़े रहने को जगह नहीं मिली। बीच बीच में आदमी उतरते रहते हैं चढ़ते रहते हैं, उनके टिकट बराबर नहीं बनाने की शिकायत आम रही है। वे और उन्हें गुसाईसर, टीडीयासर बोरमाल, कल्याणपुरा रालेसम्बसर, पलसाना उतारा गधजे सोपड़ों रहीं है। काफी पैसा अपनी जेब में ही रख लेते हैं। इससे तो लगता है कि इससे बढ़कर और कोई फैमीन नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हमें इसमें नौकरी मिल जावे। यह अव्यवस्था है इस रोडवेज में। जब तक अधिकारी लोग लापरवाही से काम लेंगे तो सरकार को नुकसान होगा और साथ में बदनामी भी होगी। यह धन्धा अधिक दिन चलने वाला नहीं है। इसमें सुधार किया जावे।

इन्हीं शब्दों के साथ में राज्यपाल महोदय, ने जो अभिभाषण यहां दिया था उसके लिये धन्यवाद के लिये जो प्रस्ताव श्री गोटेवालाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द!

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता था कि कितने सदस्य आज की बहस में भाग लेना चाहते हैं। तो समय निर्धारित करदूं। जो बोलना चाहें वे खड़े हो जायें।

श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : 13 मिनिट बाकी हैं आपके।

एक माननीय सदस्य : पूरा अवसर दीजिये साहब, आज तो लोग बहुत कम आये हैं, जो आये हैं वे बोलने के लिये ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो समय बताया है।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बड़ा कष्ट उठाकर अपना अमूल्य समय निकाल कर अपने दायरे में गिरफ्त में रह कर यहां अपना अभिभाषण दिया। इसे पढ़ने में ऐसा लगता है कि यह सारी ही निराशाजनक तस्वीर उन्होंने अपने राज्य की हमारे सामने रखी है। या यों भी कह दें तो गलत नहीं होगा कि मात्र रस्म अदायगी उन्होंने की है। सरकार आगे क्या करने जा रही है इसका आभास इससे कतई नहीं मिलता। आज जो महंगाई और अभाव की स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए यह सरकार क्या करने जा रही है यह कुछ नहीं बताया गया, इन्हें रोकना सम्भालना इस सरकार के बूते

(श्री केसरीमल)
की बात है भी कि नहीं यह भी इस से पता नहीं लगता।

स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के बाद जब नये मुख्य मंत्री ने अपना पद सम्भाला था तब घोषणा की थी कि अब महंगाई कम होगी। प्रगतिशील कदम उठाये जावेंगे। कई सुधार के कानून लाये जावेंगे। पंचायतों आदि के चुनाव भी कराये जायेंगे। हमने सोचा चलो छोड़ो पीछे की सारी बातें। आगे देखो। पर आगे के लिए देखने को इस अभिभाषण में मुझे कुछ नहीं मिला। दिशाहीन व्यक्ति की तरह यह सरकार एक जगह खड़ी है। किधर चलना है इसका इसे भान नहीं है। वक्त जरूर जा रहा है पर किस दिशा में जाना है इसका भान इस सरकार को नहीं है।

मेरा एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि हमारे प्रान्त की हालत खराब हो गई है। यहां पर लगातार अकाल पड़े हैं। अभिभाषण में भी यह बात कही गई है। मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे इलाके में लगातार अकाल पड़ता आया है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार उसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है। इन अकालों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है। अगर योजना नहीं बनायेंगे तो हर वर्ष अकाल पड़ते रहेंगे। अन्यथा ऐसे काम का कोई निपटारा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि कुदरत अकाल डालती है। आज के समाज में, आज के जमाने में कुदरत को बदला जाता है। अगर हम चाहें तो इसे कुदरत से मुक्त कर सकते हैं। चाहे हमें गंगा जमुना का पानी लाना हो। हमें इस योजना को पूरा करना है। हम सरकार को ताकीद करें। केन्द्रीय सरकार की ढिलाई के कारण हमको ऐसी योजना को लाना है। राजस्थान नहर को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर वह योजना पूरी हो जाती है तो वह इलाका हरा-भरा हो सकता है। वहां पर कपास और नरमा पैदा हो सकता है। नारंगी और माल्टे पैदा हो सकते हैं। इससे न केवल सुविधायें मिलेंगी बल्कि पूरे देश को हम दे सकते हैं। राजस्थान सरकार दो करोड़ रुपया लगाने की बात कर रही है। वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस सरकार की रेंगते-रेंगते काम करने की नीति है। इसी तरह से वह करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल को दूर करने की योजना बनाई जाये। 25 साल में सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना बनाने की कोशिश नहीं की है। मैं आपके जरिये से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह योजना को इस प्रकार से बनाये जिस प्रकार से युद्धस्तर पर काम किया जाता है। तो अकाल से पीछा छुड़ाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य खोले तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ सिवाय तालाबों से मिट्टी निकालने के। जरासी हवा चली और मिट्टी उसमें वापिस गिर जाती है। वह फिर पूरा हो जाता है। मैं देखता हूं जो पैसा लगाया जाये वह इस तरह से लगाया जाये कि उसका सही तरीके से उपयोग हो। हमारे ब्यावर और जवाजे की तरफ सेरड़ा फीडर के काम को आधा ही छोड़ दिया। ऐसे बांध बनाये कि आधे बना कर ही छोड़ दिये। आखिर यह योजना कैसे बनाते हैं। यह योजना बनाने वाले कौन

Page No 16

(16)

(श्री केसरीमल)

हैं ? यह बनाने वाले और सुझाव देने वाले कौन थे ? जिससे कि इस तरह से पैसे का खर्चा करवाया गया। मैं मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी को कड़ी सजा दी जाये। चुनाव के दौर में लोगों को खुश करने के लिए ये झूठी योजनाएं बनाते हैं। अधिकारी लोग नेताओं को गुमराह करते हैं। मैं चाहूंगा कि आगे जो योजनाएं बनायें, वह ठोस योजनायें बनायें। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में पहले भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाद में खूब पैसा खाया गया है लेकिन जिन मजदूरों ने वहां पर काम किया है, उनको अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। ऐसे हजारों मजदूर हैं उनको कहा जाता है कि तहसील में आओ। 40 मील दूर का आदमी तहसील में पैसा लेने के लिए किस प्रकार से आ जायेगा। क्यों नहीं उनको पैसा दिया जाता है। क्यों नहीं आदमी को भेजकर पैसा चुका दिया जाता है। जिन जिन गांवों का पैसा है, अध्यक्ष महोदय, उन गांवों में आदमी भेज कर पैसा चुका दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो आदमी वहां काम करते हैं, उनको पैसा नहीं चुकाया जाये तो उनको तकलीफ होती है। मेरा यह निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, इस दफा, हमारे इलाके में भी लगातार अकाल तो पड़ता ही है, वहां शीत लहर से काफी नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि वहां व्यक्ति लगातार वर्षों से अकाल पीडित रहा है। अच्छी वर्षा हुई तो भी वहां अकाल पड़ा है। इसका मतलब यह है कि फिर इन लोगों से कैसे लेवी वसूल की जाये। कैसे वह अपना पुरना चुका देंगे। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जिस इलाके में लगातार अकाल हो। आप उनको राहत नहीं देना चाहते हैं। आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं उस इलाके में लोगों के पास काम नहीं है। वह क्या करेंगे। सरकार को लिखो तो वह जवाब भी नहीं देंगे। सरकार का यह रुख है कि अगर एम. एल. ए. चिट्ठी लिखे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आजकल कागज को कीमत है। किसी मन्त्री को 10 दफा लिखा जाये तो भी जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे इलाके से मन्त्री से बात करने के लिए आये तो 4 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार से 16 रुपये खर्च होता है। आप कोई समय निर्धारित कर दीजिए तो उसके लिए 10 दफा पत्र लिखो। तो भी मन्त्री यह नहीं लिखते हैं कि फलां तारीख को मिल लेंगे। यह जिस राज्य का हाल हो उस राज्य का क्या कहना है, जहां मंत्री ऐसे हों जिनको मिलने को फुर्सत नहीं हो। जब टेलीफोन करें घर पर तो यह जवाब मिले दस बजे भी कि बाथ रूम में हैं। नाश्ता भी कर रहे हैं तो कहेंगे कि बाथरूम में हैं....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अब सरक्यूलर निकाल दिया है कि यह कहें, पूजा में हैं।

श्री रामकिशन : अब बन्द कर दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब पूजा ज्यादा हो गई है।

एक माननीय सदस्य : पूजा वाले तो हट गये।

श्री केसरीमल : आप कह रहे हैं कि लम्बी लम्बी पूजा करने वाले हट गये। मेरा निवेदन है कि लम्बी लम्बी पूजा करने में ही न रह जाय नहीं तो कोई कुर्सी छीन कर ले जायेगा। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मंत्री जी को मिलने का अवकाश नहीं है–ऐसी बात नहीं हो।

यह जो कहा जा रहा है कि यह महंगाई बढ़ रही है, यह कुदरत की वजह से बढ रही है, इसको मैं नहीं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह महंगाई बनावटी महंगाई है। जमाखोर हैं और सरकारी मशीनरी में सरकार में बैठे हुए हैं वह आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने ही इस महंगाई को पैदा किया है। सरकार ने और राजनेताओं ने इस महंगाई को पैदा किया है। ऐसे-ऐसे राजनेता हैं जिनका स्वार्थ इन जखीरेबाजों के साथ बंधा हुआ है, वह इन सरमायेदारों के साथ में मिले हुए हैं। उनका स्वार्थ इस वर्ग के लोगों के अन्दर रहा है इस वजह से ही अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकने हैं। उनका अपना स्वार्थ है इसलिए आज वह बोल नहीं सकते हैं। आज राजनेता और वह वर्ग एक साथ हैं। यह लोग कभी नहीं चाहते हैं कि अनाज की वसूली हो, लेवी की वसूली ठीक तरह से हो जाय, प्रोक्योरमेंट सही ढंग से हो। वह यह नहीं चाहते हैं वह नहीं चाहते हैं इसलिए वसूली नहीं हो रही है। इसमें राजनेता और उस मशीनरी का हाथ है, जिनका दिमाग, जिस तरह पुराने आई. सी. एस. आफिसरों का होता था, जिनके दिमाग में अंग्रेजीयत की बू भरी हुई थी, जो आज के हिन्दुस्तान को नहीं समझ सकते थे, स्वतंत्रता के बाद में आये हुए अधिकारी भी उनकी तरह के ही हो गये हैं। इसके अलावा जो अधिकारी आये हैं वह ऐसे ऊंचे घरानों के हैं, पैसे वालों के हैं, जागीरदारों के हैं और बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के आफिसर हैं। ऐसे अधिकारी जब तक रहेंगे तब तक वह यह कभी नहीं सोच सकते हैं कि आज समाज में किस बात की आवश्यकता है, हमें समाज को किस ढांचे में ढालना है। वह तो अपने अपने महल बनाने में लगे हुए हैं। एक एक इंजीनियर, जिसकी तनख्वाह चार सौ रुपये है, उसके मैं पांच लाख के बंगले देखता हूं। एक इन्सपेक्टर, जो दूध की जांच करने वाला इन्सपेक्टर होता है, मैंने कुछ जगहों पर उनके मकान देखे हैं। जो ओवरसियर हैं, इनके भी लाखों रुपयों के बंगले बने हुए हैं, इससे पता लगता है कि कितनी

(10.02 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

यह नौकरशाही भ्रष्ट होकर इस धन्धे में लगी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आपस में मिल कर महंगाई को बढ़ाया है।

आज किसी चीज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज चाहिए, वह मिलेगी, लेकिन मिलेगी उस भाव से, जिस भाव से वह बेचेंगे। इसलिए ही अपने यहां बनावटी कमी दिखाते हैं। मुझे मालूम है, एक घटना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोयले की बड़ी सख्त जरूरत थी, कोयले के डिब्बे रेल्वे में आये हुए पड़े थे, लोगों ने आशा की थी कि कोयला अब शहर में आ जायगा और

(श्री केसरीमल)

कारखानों की भट्टी और घरों के चूल्हे ठण्डे नहीं रहेंगे। कोयला रेल्वे के डिब्बों में पड़ा हुआ है। एस. ओ. से कहा गया कि कोयला आ गया है, बिल्टी आ गई है, लेकिन कोयला छूट कर क्यों नहीं आया है, बिल्टी क्यों नहीं छुड़ाई है। लोग इस आशा में खड़े थे कि अब सस्ता कोयला हाथ में आयेगा। लेकिन वह कोयले की बिल्टी तीन दिन तक नहीं छुड़वायी गई और शहर में जो कोयला था, वह कोयला दूने भावों पर ब्लेक किया गया, लोग उसको बेचते रहे और जिनको जरूरत थी, उनको वह लेना पड़ा। व्यापारियों ने सोचा कि डेमरेज लगेगा, वह दे देंगे, डेमरेज कितना लगता है, जब कि मुनाफा ब्लेक मे बेचने से काफी मिलता है। यह जो जरायम पेशा लोग हैं, जालिम लोग हैं य. मुनाफा कमाने के लिए, चोर बाजारी करने के लिए लोगों को भूखों मारने के अपराधी हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। सरकार पंगु है और यह सरकारी मशीनरी है यह उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। मेरा निवेदन है कि जो सरकार एक्शन नहीं ले सकती है, वह सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जमाखोर लोग इस तरह अपने आप बनावटी कमी दिखाकर लोगों को भूखा मारने की बात करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हड़ताल और बन्द यहां होते हैं, अभी दो मार्च को इसलिए बन्द हुआ कि महगाई बढ़ती चली जा रही है। लोग कहते हैं कि कर्मचारी अपनी-तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं। हम तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। जो मजदूर है, या कर्मचारी है, वह इसलिए तनख्वाह बढाने की बात नहीं करते क्योंकि खाली तनख्वाह बढ़ने से कुछ नहीं होता। जो ढाई सौ तीन सौ रुपये की तनख्वाह पाते हैं उनका जीवन इससे सुखी नहीं होता, उसकी तनख्वाह कुछ बढ़ जाय तो भी वह आज सुखी नहीं है। इसलिए तनख्वाह बढ़ाना ही इस बीमारी का इलाज नहीं है। यह इलाज भी नहीं है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। इस महंगाई के भूत को तो संघर्ष करके मारना चाहिये। इसका इलाज है कि अपने देश से शोषण समाप्त कर दिया जाय। शोषणविहीन समाज बना दिया जाय। तभी इसका इलाज होगा। इस बीच जो महंगाई हुई है, वह क्यों हुई है। वह महंगाई हुई है दूषित वितरण व्यवस्था से। आज मिल का मजदूर हो या कोई कर्मचारी, हर एक इन्सान यह मांग करता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे बारह किलो अनाज मिले और एक किलो चीनी मिले। इस तरह की सरकार व्यवस्था करे। सरकार कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते। हमको तो केन्द्रीय सरकार जो देगी वह देंगे। इस तरह तो आप हथियार डाल कर खड़े हो गये तो यह जरूरी बात है कि ऐसी हालत में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार आपके सामने आयेगा। ऐसी लुंज पुंज राज्य सरकार को तो कोई भी आकर धक्का देने की कोशिश करेगा। यह मौका है जिसका प्रतिक्रियावादी ताकतें बेजा फायदा उठा सकती हैं। आज देख रहे हैं प्रतिक्रियावादी ताकतें इसका बेजा फायदा उठा रही हैं। उन्होंने हालत को ठीक करने के बजाय और हालत को बिगाड़ने की कोशिश की है। थोड़े दिन पहले 27 तारीख को ब्यावर में

(श्री केजरीमल)

जनसंघ ने, कुछ विद्यार्थियों ने बन्द करवाया। इन एण्टी सोशल लोगों ने पत्थर फेंके, वह कहां फेंके, मोटरों पर, रैल्वे पर पत्थर फेंके। मिल में गये वहां मशीनरी तोड़ने का प्रयास किया। जो कूलर बाहर लगा हुआ था, उसको तोड़ा। गेट भारी था, इसलिए अन्दर नहीं पहुँचे, नहीं तो उन्होंने प्रयास किया कि कारखाना लूटें। मैं कहना चाहूंगा, जनसंघ ऐसी प्रतिक्रियावादी पार्टी है, वह इस बात का विचार करके चलती है कि हम इस हालत में ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्थिति को पैदा कर दें, जिससे जो सरकार बिल्कुल नाकामयाब है, जिस सरकार में कोई दम नहीं है, जो सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इस सरकार को धक्का दें और यह सरकार तिलमिला कर रह जाय। और बाद में अपने ढंग से सब बातों को करें। यह तौर तरीका है। इसके पीछे बड़ी राजनीति है। बैंक इसलिए जलवाये जाते हैं ताकि बनियों के खाते समाप्त हो जायें। मोटरों में आग इसलिए लगवाई जाती है ताकि टाटा की मोटरें ज्यादा बिकें। इनकी मन्शा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकृत उद्योग समाप्त हो जाय। मिल और कारखाने इसलिए तोड़ेंगे कि जिससे उत्पादन कम हो। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य यह नहीं। हम भी लड़ते हैं और लड़ेंगे। उदाहरण के रूप में 2 तारीख का बन्द है। लेकिन दो तारीख को राजस्थान में एक भी घटना नहीं हुई। ब्यावर बन्द में इतनी घटना हो गई। दो तारीख के बन्द की खिलाफत में इन्होंने आन्दोलन करने का नारा दिया, उसमें लोगों के सिर फोड़े। इसलिए इनके तौर तरीकों को समझने की जरूरत है। भीलवाड़ा के अन्दर राजस्थान बन्द के अन्दर विद्यार्थियों ने मारपीट की। एक बैंक का कर्मचारी है, बलराम (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, पांच सात मिनिट····

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है। आपके दल का समय था, उससे ज्यादा दे चुका हूं।

श्री केसरी मल : थोड़ा सा और। इन्होंने लोगों के सर फुड़वाए और जो उसको टांके लगवाने जा रहा था उसका भी सर फोड़ दिया। इस तरह से मेड़ता में विद्यार्थियों के साथ मारपीट की, जहाजपुर में मारपीट की। 2 तारीख का बंद हमने इसलिए किया क्योंकि मजदूर किसान राज्य कर्मचारी इस बात को मानकर चलते थे कि पर्याप्त राशन मिलना चाहिए और जो राशन के समान को छिपाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों के पक्ष में इन लोगों ने मारपीट की। अभी तो इनके पास ताकत नहीं तो भी इतनी मारपीट करते हैं। इंदिरा गांधी के लिए कहते हैं कि उनका हैलीकोप्टर उत्तर प्रदेश में उतरेगा तो हम गोली मार देंगे। ऐसे लोग जनतंत्र की दुहाई देते हैं जिनका दिमाग, जिनकी बात, जिनके विचार बिल्कुल फासिस्ट हैं किसी को हैलीकोप्टर से उतरना नहीं देना चाहते। भारत के रेडियो की आवाज बंद करना चाहते हैं, हैलीकोप्टर को गोली मारना चाहते हैं। जब ये लोग ताकत में नहीं हैं तो यह

(20)

श्री केसरीमल

है लेकिन अब इनके हाथ में राज्य आएगा तो ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ऐसे फासिस्टों को कांग्रेस बरदाश्त करती है राज्य सरकार ऐसे हालात बना देती है ऐसे लोगों को तरजीह दे रही है इसमें कोई शक नहीं है।

श्रमिकों के बारे में निवेदन करूं कि इस सरकार ने उनके बारे में कोई नीति नहीं अपनाई। यह सरकार बार बार कहती है कि समाजवादी ढांचे की ओर जा रहे हैं। मैं कहता हूं समाजवाद की बात तो छोड़िए ये अपने को अच्छा पूंजीपति साबित नहीं कर सकती। कई पूंजीपति अच्छे उद्योग चलाते हैं। उद्योग चलाने वाले अपने यहां कर्मचारियों को कैसे डील करते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन ये राज्य के पूंजीपति जो अपने कारखाने चलाते हैं निकृष्ट तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान रोडवेज एक यूनियन एटक की जिसके सदस्य बहुमत में हैं 90 प्रतिशत है और दूसरी इंटक की यूनियन के 10 प्रतिशत सदस्य हैं। मैनेजमेंट आज भी इंटक के हाथ में है हमारी यूनियन का बहुमत है तो भी लिया जाएगा इंटक का आदमी। हमारे मुख्यमंत्री ने विजयनगर के सम्मेलन में जो कुछ यूनियन्स के बारे में कहा उसका मतलब दूसरी यूनियन को क्रश करो, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। अगर राजकीय नीति यही रही तो दूसरी यूनियन्स के साथ अन्याय किया जाएगा। तब फिर आप कहते हैं कि हड़तालें नहीं होनी चाहिए कहते हैं कि रांड तो रंडापा काट ले लेकिन रंडुवे काटने दें तब ना, मजदूर तो हड़ताल नहीं करें लेकिन यदि आप ऐसी स्थिति पैदा करें तो हम उसका क्या इलाज करें ?

श्री उपाध्यक्ष : आप शायद होली के मूड मे हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम खड़ा होता हूं। आज जितने राजकीय उद्योग हैं उनमें हजारों लोग ऐसे हैं जिनको वाजिब हक नहीं मिल रहे हैं। चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग में, चाहे विद्युत मण्डल में, वहां काम करने वाले हजारों लोग जो हैं एक जैसा काम करते हैं जैसा खड्डा खोदने वाला एक स्थाई आदमी काम करता है वैसे ही एक अस्थाई आदमी काम करता है लेकिन उसको वे अधिकार नहीं मिलते। कहते हैं कि ये केजूएल हैं, टैम्प्रेरी हैं, डेली-रेटेड हैं। इस बीच में कुछ यूनियन्स के जरिए कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार खुद ऐसे धंधों में जहां हजारों लोग काम करते हैं, उनको स्थाई करे और स्थाई कर्मचारियों जैसी सुविधायें दें। वाटर वर्क्स में शहरों और कस्बों के कर्मचारियों के मुकाबले गांवों में एक एक आदमी 24 घंटे स्टेशन संभालते हैं उनको वे सुविधायें नहीं मिलती हैं क्योंकि वह गांव में रहता है क्योंकि फिक्सेशन नहीं हुआ, स्थाई नहीं हुआ। जब काम एक जैसा है तो एक ही ढंग से सबको रखना चाहिए।

विद्युत मंडल के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। वहां रिश्वतखोरी हद दर्जे की हो गई। 5 हार्स पावर कनेक्शन के लिए किसान से इंजीनियर की अलग

Page No 21

(21)

(श्री केसरीमल)

फीस, 10 हार्स पावर के लिए अलग फीस लेकिन घर के बिजली के कनेक्शन के लिए भी जब तक 20) पर कनेक्शन नहीं दे दिए जायं जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो कर्मचारी वहां काम करने वाले हैं उनके साथ बड़ा अन्याय किया जाता है। वहां भी मजदूरों को पूरी सहूलियतें नहीं दी जाती हैं, तनख्वाहें कम हैं। इंटक के लोगों ने राज्य सरकार से समझौता किया जिसके अनुसार 140) न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। कहीं भी किसी उद्योग में इतना कम न्यूनतम वेतन नहीं है। उसके बाद मजदूर लड़े, सारे देश में मजदूर लड़े, केन्द्रीय सरकार ने समिति बिठाई 30 रु. अंतरिम सहायता स्वीकृत हुई, यहां के लोग देने को तैयार नहीं थे अब घोषणा की है इंटक को साथ में लेकर, समझौता किया जाता है। इंटक के साथ और इंटक के लोगों की एक कमेटी बनती है जिसके अन्दर प्रोमोशन स्थाईकरण और दूसरे मामले जो भी हैं, सारे फैसले इंटक का आदमी बैठकर उसमें हल करने की बात करता है। कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि इंटक में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को मजबूर करें, ऐसे लोग मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसे लोग जिनका हक नहीं है, वहां पर लाइनमैन बना देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कर्मचारी कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे अदालत में जाने दीजिये तो श्रम विभाग उनको न्यायालय में जाने से रोकता है। आप उसको हक नहीं दे सकते तो फिर वे हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे या तो वह चुपचाप भूखे मरें। मजदूर इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही एम.टी.सी. कारखाने में वहां इंटक की यूनियन के 15 आदमी होंगे और सैंकड़ों आदमी दूसरी यूनियन के, लेकिन दूसरी यूनियन की मान्यता छीनकर इंटक को दी गई। इतना ही नहीं, दूसरी यूनियन के लोगों पर कातिलाना हमला किया, जान से मारने की कोशिश की, सरियों से वार करवाया और पुलिस के जरिए दमन करवाया, झूठे मुकदमे करवाए, इस तरह का रास्ता यदि खुद सरकार पकड़ेगी तो यह कौन सा रास्ता है, कहां ले जाएगा ?

इन्जीनियरिंग विभाग के मजदूरों के भी झगड़े हैं लेकिन अब समय नहीं है। यहां के एक बड़े कारखानेदार हैं जिसको सरकार ने जमीन कर्मचारियों के क्वार्टर्स बनाने के लिए 1–1।। रुपये गज में दी, वह जमीन उनके पास है, वहां उन्होंने मकान नहीं बनवाए कर्मचारियों के लिए और सरकार को धोखा दिया, उस जमीन को उसने हड़प रखा है। आज उस जमीन को 60–70) रुपए गज में बेचा जा रहा है और लाखों और करोड़ों रुपए वह इकट्ठे कर रहा है। उसका नाम है ए.सी. मुखर्जी। मेरा निवेदन है कि तुरन्त उस जमीन पर कब्जा किया जाए, उसको बेचने से रोका जाए, जो जमीन बेची है उसको वापस किया जाए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और कह कर बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका अन्त नहीं है फिर तो। श्री राम किशन शर्मा।

श्री राम किशन (भरतपुर) : मैं अपने को शर्मा नहीं कहता। जातिवाद के खिलाफ हूं।

Page No 22

(22)

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला ने राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव इस सदन में रखा और मैं उस प्रस्ताव का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव क्यों? इस सदन की परम्परा आखिर क्या है? इसकी जरूरत क्या है? आखिर वह अपने भाषण में सिर्फ यही तो कहते हैं कि राज्य सरकार ने पिछले साल क्या किया और उसकी उपलब्धियां क्या रहीं और अब आगे उसमें क्या परिवर्तन राज्य सरकार करने जा रही है। राज्य सरकार का अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। अगर इस तरह भाषण से ही वह हमें जानकारी इन्हीं बातों की देना चाहते हैं कि इतने सीमेण्ट के कारखाने खुलेंगे या तेन्दू के पत्ते का राज्य सरकार अब राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो इसके लिये राज्यपाल महोदय को यहां आकर भाषण देने की जरूरत नहीं थी। वह उसे अखबार में ही छपा लेते और हम उसे अखबारों में पढ़ लेते। इसके लिये इस सदन को बुलाकर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मैं इसकी आवश्यकता बिलकुल नहीं समझता।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा से हर साल जब भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में होता है तो उस किताब में यही पढ़ा जाता है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, हम सामन्तवादी परम्पराओं से निकल कर आये हैं, और राजस्थान एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। मैं भी यह मानता हूं कि हम सामन्तवादी परम्पराओं से निकल कर आये हैं, अकाल यहां पर हर साल पड़ता है, कई जगहों पर बाढ़ भी आती है और रेगिस्तान यहां पर बहुत बड़े हिस्से में है। अगर इन तीनों बातों को दोहरा कर बार बार राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है तो बात दूसरी है, अन्यथा मैं तो यह कहना चाहूंगा आखिर आपने इन दोषों को मिटाने के लिये क्या किया? कल मैं तो यहां था नहीं, कहीं पर बाहर गया हुआ था और इस सदन में श्रीमती सुमित्राजी ने अपना भाषण दिया उसमें भी उन्होंने कई बातें कहीं। कुछ अच्छी बातें भी कहीं लेकिन यह कहना वह नहीं भूलीं, राजस्थान में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और यह एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। मैं भी इसे मानता हूं। यह हकीकत है कि हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है और हम सामन्ती दौर से गुजरे हैं लेकिन यही गाना गाने से क्या फायदा? आखिर इसका अन्त कब होगा? आखिर यह पिछड़ापन कब खतम होगा? और विकास कितने दिनों बाद इसका होगा? इसका विकास तो होना चाहिए। आज कौनसा ऐसा देश है जो कि सामन्ती दौर से इस दुनियां में नहीं गुजरा है? दुनियां का हर देश इस दौर से गुजरा है। आज इतने वर्ष हमें आजाद हुए हो गये लेकिन हम अभी तक वहीं पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी परसों ही पूनमचन्द विश्नोई ने इस सदन में अपना भाषण दिया। मैं उनकी कद्र करता हूं लेकिन उन्होंने भी वही गाना गाया जो हमेशा से कांग्रेस गवर्नमेंट गा रही थी कि हमारे यहां देश की पोपूलेशन ज्यादा हो गयी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है

(श्री रामकिशन)

कि विश्नोईजी जैसे समझदार यह बात बतला रहे हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ गयी। इतना तो मैं भी समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ गयी है। इसको मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे उन्होंने बताया कि हमने इतने बान्ध बनाये और इतनी सड़कें बनायीं। तो मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि इन बातों को हमें बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो क्या, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति यह जानता है कि आबादी बढ़ी है, रेगिस्तान है, सड़कें बनी है। लेकिन उन्हें तो यह बताना चाहिये कि कौनसे रास्ते अपना सकते हैं जिससे कि यह पिछड़ापन समाप्त हो सकता है और विकास हो सकता है। सिर्फ हर कांग्रेसी सदस्य का यह कह देना तो गलत है कि सामंती दौर से गुजरा, या पूंजीवादी दौर से गुजरा। और देशों का भी विकास हुआ है। अभी मैं सदन में रूस का नाम लूंगा तो यह कह देंगे कि वह तो कम्युनिस्ट हैं, अगर अमेरिका का नाम लूंगा कि वहां विकास क्यों हुआ तो कहेंगे कि वहां पूंजीवाद है। खैर उनकी बात मैं नहीं करता लेकिन मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बर्मा जैसे देश ने तरक्की कैसे की? तो कहेंगे कि वह छोटा देश है। अगर इजरायल का नाम लूंगा तो कहेंगे कि वह छोटा देश है। अगर इजरायल का नाम लूंगा तो कहेंगे कि उसको विदेशों से मदद मिली खैर किस देश ने कैसे उन्नति की उसकी चर्चा अभी यहाँ पर नहीं कहीं करूंगा। मुझे खुशी है कि यहाँ पर सभी बोलने वाले सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और जो भी हमने आज तक उपलब्धियां की हैं वह कम हैं। उनको इस बात को स्वीकार करने के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक व्यक्ति मंत्री होता है तो उसके बोलने की अदा और होती है, वाणी और होती है, बात करने का ढंग अलग होता है लेकिन जब वह मन्त्री पद से मुक्त हो जाता है तब उसके बोलने की वाणी अलग हो जाती है, उस वक्त उसे राजस्थान का पिछड़ापन, और उसकी दिक्कतें क्या है–सभी बातें याद आ जाती है। इसके अलावा श्रीमती सुमित्राजी ने अपने भाषण में आंकड़े पिछड़ेपन के राजस्थान के दिये उसके लिये उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह आंकड़े मुझे देने पड़ते अच्छा हुआ कि मेरा बोझ हलका हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम हमारी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो योजना बनी है उसमें सार्वजनिक उद्योगों पर पूंजी का नियोजन कम किया है। और राजस्थान को तो उसमें बहुत ही कम मिला है। इसके लिये मैं सुझाव राज्य सरकार को, चाहे आपके मार्फत समझें, चाहे माननीय सदस्यों के मार्फत, मैं यह देना चाहूंगा कि हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने हमारा पक्ष रखने में हमेशा कमजोर रही है। आपको जाकर केन्द्रीय सरकार को समझाना चाहिये कि राजस्थान एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, वहां पिछड़ा वर्ग अधिक है, वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री रामकिशन)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की आबादी अधिक है, इसकी वजह से काफी संकट पैदा होते हैं। इसके लिये हमें विकास के लिये अधिक पैसा मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे को केन्द्र से ज्यादा मदद नहीं मिलने का कारण यह है कि हमारे यहां का जो मुख्य मन्त्री रहा है वह हमेशा छोटा रहा है केन्द्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री के मुकाबले में। छोटे से मेरा मतलब यह नहीं कि वह कद में छोटा है, छोटे से मेरा मतलब व्यक्तित्व से है, योग्यता से है। इसके अलावा हमारे राज्य को केन्द्रीय सरकार से पैसा कम मिलने का एक कारण और है और वह यह कि जब अंग्रेज भारत में आये तो हिन्दुस्तान में दो तरह के व्यक्ति उसे मिले, दो तरह के इलाके मिले। एक तो उस जगह के व्यक्ति जिन्होंने, कि आते ही अंग्रेजों को पनाह दी, धन से दोस्ती के हाथ बढ़ाये। पहले में उन्हें ले लेता हूं जिसमें अपने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और लाहोर वाला इलाका और वहां के लोग आते हैं। दूसरा वह इलाका जिसमें राजस्थान और यू.पी.; बिहार और उड़ीसा वगैरह प्रान्त के लोग आते हैं। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लाहोर वगैरह में ज्यादा से ज्यादा कारखाने वगैरह लगाये और वहां का विकास अधिक हुआ। चूंकि यू. पी. और राजस्थान वगैरह ने, जो कि हिन्दुस्तान की वह जनता थी, जो कि हिन्दी भाषी लोग थे, उसको सहयोग नहीं दिया अतः उन्होंने यहां पर विकास का कार्यक्रम उनकी अपेक्षा कम किया। उसके बाद हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो वह कार्यक्रम उसी तरह चलते गये। कांग्रेस राज्य की सरकार ने भी उसी ढर्रे को जारी रखा। आप चाहे तो अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखें तो आपको पता लग जायेगा उनके आंकड़ों से, इसमें जो हिन्दी भाषी इलाका था उसमें सिर्फ उन योजनाओं का सिर्फ 20 प्रतिशत ही पैसा खर्च किया गया और अहिन्दीभाषी इलाकों पर योजना आयोग ने 80 प्रतिशत रुपया खर्च किया। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको केन्द्रीय सरकार पर ज्यादा दबाव डालना चाहिये और यहां विकास का कार्यक्रम ज्यादा होना चाहिये।

तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां का जो मुख्य मन्त्री है वह हमेशा से ही चूंकि छोटा रहा, उसको हमेशा यही खतरा बना रहता है कि कहीं प्रधान मंत्री से मैं अटकूंगा तो मेरी हुकूमत चली जायेगी और अपने आप को हमेशा छोटा ही मानते रहे, अपने को बराबरी से नहीं समझा। किसी भी मुख्य मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री से इस बारे में कभी टक्कर नहीं ली क्योंकि वह छोटे थे चाहे आचरण में समझें, चाहे योग्यता में...

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): तो फिर यू. पी. का विकास क्यों नहीं हो सका जब कि वहां का तो प्रधान मन्त्री ही होता है?

श्री रामकिशन: आप स्थान ग्रहण करें। आप कभी मुख्य मन्त्री नहीं बने। आप तो बहुत छोटे हैं। आप तो अभी लूणकरणसर अपने घर में ही बैठे हैं।

तो मैं कह रहा था कि यहां के मुख्य मंत्री छोटे रहे जो सिर्फ अपने पद को ही कायम रखने में रहे और केन्द्र की हां में हां मिलाते रहे। मजबूती से राजस्थान का पक्ष पेश नहीं कर

(श्री रामकिशन)

सके । और ऐसे समझते रहे कि कहीं हमारी कुर्सी चली गई तो हमारा प्राणान्त हो जायेगा। हम समाज में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसा कि अभी श्री भीमसेन जी ने कहा कि यू.पी. का विकास क्यों नहीं हुआ, वहां तो हमेशा ही मुख्य मंत्री अच्छा रहा होगा, मजबूत रहा होगा। यह ठीक है लेकिन अगर यू. पी. का विकास अधिक करते तो दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्री जैसे बिहार का है, वह कहता आपका जो प्रधान मंत्री बन गया फिर क्या चाहिये? आसाम का मुख्य मन्त्री कहता कि यू. पी. का प्रधान मंत्री है तो तेल का कारखाना आसाम में लगेगा। उड़ीसा का मुख्य मंत्री कहता है कि इस्पात का कारखाना उड़ीसा में लगेगा। इसलिये यू.पी. का प्रधान मंत्री होना ही उसके लिये और प्रगति होने के लिये अभिशाप बन गया। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे राजस्थान की दिक्कतों को केन्द्र के सामने ठीक तरह से रखा जाता तो हमारा विकास अधिक होता। उपाध्यक्ष महोदय, केवल पिछड़ापन कहने से काम नहीं चलता। चीन भी तो एक देश है, हमारे बाद में आजाद हुआ लेकिन हमारे से ज्यादा तरक्की उसने की है। ज्यादा उत्पादन वहां का बढ़ा है, ज्यादा विकास हुआ है। वैसे मैं कोई चीन और रूस का हिमायती नहीं हूं लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि हमारे देश का, हमारे प्रान्त का विकास होना चाहिये। केवल भाषणों से विकास नहीं होने की है। अभी की पंचम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त का विकास करने के लिये कितनी अधिक धनराशि दी गयी; यह देखने की बात है। मैं समझता हूं कि हमें मदद कम दी गई है। और हमारे यहां मुख्य मंत्री इस पर ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हमारे यहां के मुख्य मंत्री को तो अपने पद की फिक्र रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब कुछ समय पहले हमारे यहां मुख्य म[ंत्री] का पद रिक्त हुआ था तो मैंने अखबारों में जो विचारधारायें पढ़ी है उसमें इस बात पर जोर था कि जाट मुख्य मंत्री नहीं बने, दूसरी यह कि जाट बने। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज जमाना कितना आगे बढ़ गया है, इस वक्त भी यह लोग जाट और गैर जाट, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात करते हैं। मेरे अनुसार तो कोई मुख्य मंत्री हो पर राजस्थान का विकास करने वाला हो। अभी, उपाध्यक्ष महोदय, पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पिछड़ेपन और आबादी के हिसाब से ढाई प्रतिशत लोग माने हैं। आज राजस्थान की दो करोड़ और 57 लाख के करीब जन संख्या है। आंकड़ों के अनुसार 10 पर्सेन्ट लोग गांवों में पिछड़े और गरीब हैं और शहरों में 50 प्रतिशत, पर मैं राज्य सरकार के इन आंकड़ों को सही मानने को तैयार नहीं हूं मैं 2 करोड़ 57 लाख में से एक करोड़ और 58 लाख आदमियों को गरीब मानता हूं। तो पहली, दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसमें बदलाव करें और पांचवी योजना के अन्तिम प्रारूप में केन्द्रीय सरकार पर इसके लिये विशेष जोर देता हूं कि ज्यादा धनराशि प्राप्त हो सके।

राजस्थान नहर की चर्चा होती है। हमारे यहां केन्द्रीय उद्योग कम लगे हैं। सुमित्रा जी ने भी कहा। पिछले भाषण में मैंने डिटेल्स

(श्री रामकिशन)

बतायी थीं। इसका क्या कारण है ? यू. पी. में योजनाएं पूरी होंगी या नहीं यह मुझे पता नहीं। चुनाव से पहले जितने कारखानों का उद्घाटन कर दिया, उनका क्रियान्वयन हो सकेगा या नहीं यह मुझे पता नहीं और यदि करने की कोशिश की गई तो कहीं भीख मांगनी नहीं पड़े।

यदि केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर को अपने हाथ में नहीं लेती है तो क्या राज्य सरकार इस बात के लिये तैयार है और क्या कांग्रेस में ऐसा साहस है कि वह अलग हो जाय ? मैं नहीं समझता कि ऐसा साहस है। तामिलनाडू केन्द्र से नहीं डरता, उडीसा नहीं डरता, गुजरात नहीं डरता। केन्द्र इनसे डरता है। लेकिन राजस्थान सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। राजस्थान का कोई जोर का स्वरूप नहीं है, हमेशा मुगलों की दासता का स्वरूप रहा है। बराबरी का स्वरूप नहीं रहने से सरकार केन्द्र की सरकार को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर को केन्द्रीय सरकार ले। विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष केन्द्रीय आयोजना आयोग को समझाने की कोशिश करे और यदि नहीं समझते हैं तो आपको चाहिये कि सत्ता छोड़ दें वरना राजस्थान में कोई सुधार नहीं कर पायेंगे।

अभिभाषण में कार्यक्रम का संकेत दिया गया है उसमें केवल इसका पता है कि सीमेन्ट के कारखाने लग जायेंगे। क्या केवल इससे विकास हो जायगा ? इससे काम नहीं चलने वाला है।

हम शिक्षा के क्षेत्र को देखे तो सबसे पिछड़े हुये हैं। सिचाई के क्षेत्र को देखें तो सबसे पिछड़े हुये हैं। सड़कों के क्षेत्र को देखें तो सबसे पिछड़े हुये हैं। वित्त एजेन्सीज ने सहायता दी उनमें भी हम सबसे पीछे हैं। केवल यही कारण हम बताते है कि राजाओं के राज से आये हैं और रेगिस्तान के इलाके से आये हैं इसीलिये पिछड़े हुये हैं। रेगिस्तान हमारे लिये अभिशाप है लेकिन इजराइल के लिये वह वरदान हो सकता है। आप कह देंगे कि उसको तो अमेरिका से खूब धन मिला है। लेकिन दुनिया के 74 देशों से आपके मन्त्री भीख मांगने जाते है। आपने कुवैत जैसे देश को भी नहीं छोड़ा है।

हमें इन सारी संभावनाओं पर फिर से विचार करना चाहिये। मैं अभिभाषण का विरोध करने खड़ा हुआ तो एक माननीय सदस्य ने कहा आप तो विरोध करेंगे ही। नीतियों से विरोध है। आज देश में दरिद्रता बढ़ रही है, इतनी सड़कें बनी, इतने पुल बने। आप समझते हैं कि हमें पता हो नहीं। जो भी सरकार आयेगी वह यह बनायेगी। अंग्रेजों की सरकार ने भी उनने भी बनाये। आज कांग्रेस की सरकार है तो वह भी बनायेगी। ये निर्माण के कार्य तो जो भी सरकार आयेगी करेगी। विश्नोई साहब, चिली का उदाहरण देना चाहता हूं। चिली के शासन में क्या विशेषता थी, उसके राष्ट्रपति की क्यों हत्या कर दी गई ? विकास की गति उस छोटे से देश की अधिक थी और उसके पड़ोसी देश लेटिन अमेरिकन देशों की विकास की गति धीमी थी और इस तरह से वहां का विकास पूर्ण रूप से

(श्री रामकिशन)

हो रहा था चाहे वह छोटा सा देश हो। इसको दूसरे देश सहन नहीं कर सके और राष्ट्रपति डा. एलन्डे को हत्या करा दी गयी। उसके विरोधियों ने उसको हत्या करायी। जो विकास होता है किसी भी देश और राज्य में च हे उसकी प्रगति धीमी हो लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिये वह यह होना चाहिये कि उस विकास से अधिक से अधिक लोगों को, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को लाभ मिले। तब ही सरकार की सफलता मानी जा सकती है। लेकिन दोनों ही माने में हमारे यहां गडबड़ी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंच-वर्षीय योजनाओं में जो विकास की गति रही है 5 परसेन्ट जहां विकास की गति होनी चाहिये थी वहां हुई है 1 परसेन्ट और जहां 2½ परसेन्ट होनी चाहिये थी तो हुई है ½ परसेन्ट। यह है आपके विकास की गति की स्थिति। जो भी विकास की गति रही हो लेकिन उसका लाभ गरीब लोगों को न मिल कर अन्य लोगों को ही उसका फायदा मिला। राज्यपाल के अभि-भाषण से इशारा है कि जिसमे हम समझें कि गति कमजोर भी रही हो तो भी गरीब लोगों को फायदा होगा। मंत्री कह देंगे 25 लाख रुपया अनुसूचित जाति के मोहल्लों के लिये खर्च करेंगे। हरिजनों को छात्रवृत्ति देंगे। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि हरिजन किस प्रकार से कांग्रेस पर विश्वास करते हैं? पांच हजार वर्ष के इतिहास में दुनिया में किसी समाज का शोषण नहीं हुआ होगा जितना हरिजन जाति के लोगों का शोषण हुआ है। या तो मैं पागल हूं या समझ नहीं पाया हूं या आज भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि समझे नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले वाली बात।

श्री रामकिशन : बिश्नोईजी यहां हैं, जवाब देंगे। सम्पतरामजी ध्यान से सुन लो। 62 लाख एकड़ का आवंटन किया। भूमि-हीनों को जमीन अलाट हुई। जरा देखिये भूमिहीनों में कौन से भूमिहीन ने जमीन ली है? क्या मोहनलाल सुखाडिया, हरिदेव जोशी भूमिहीन है? इन सब ने जमीन ली है। चर्चा थोड़ी ही जानी चाहिये इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। 52 लाख एकड जमीन में से 48 लाख एकड़ जमीन तो बड़े बड़े सरकारी अफसर, व्योपारी और बड़े बड़े राजनेताओं को दे दी। 13 लाख एकड जमीन हरिजन आदिवासियों को दी गई। उनको कौनसी दी गई? जो बढ़िया जमीन थी जिनमें खेती हो सकती थी, जो उपजाऊ जमीन थी वह सब तो राजनेताओं, व्योपा-रियों और अफसरों ने मिल कर बांटली और बाकी को जमीन जो किसी गांव में रास्ते के जमीन रही है, वह आवंटित करदी आदि-वासियों को, हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को। धोबी को आवंटन हुआ रास्ते की जमीन का। वह जोतने के लिये गया। कौन उसको उस जमीन को जोतने देगा। और इसको लेकर गांव गांव मे झगड़े और मारपीट शुरू हुई कांग्रेस राज मे हरिजनों का पिछले 25 वर्षों में जितनी पिटायी हुई है उतनी अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुई। पिछले साल एक हजार हरिजन जिन्दा जला दिये गये। क्या अंग्रेजों के राज में भी किसी हरिजन को जिन्दा जला दिया गया? क्या जनाने

Page No 28

(28)

(श्री रामकिशन)

वालों को आज तक इस कांग्रेस के राज ने किसी को सजा दी ? महतर को पीट दया। 2 परसेन्ट भी ऐसे मामले बता दीजिये कि जिनमें मारने पीटने वालों को सजा हुई हो। नहीं बता सकते। हरिजन कल्याण की बातें कही जाती हैं तो दिल में बड़ा दर्द होता है। इतना व्यापक झूठ कि हम हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते है। न जाने ये हरिजन प्रतिनिधि क्यों इसको निगल जाते हैं। मंत्री महोदय नजर नहीं आवेंगे हरिदेवजी को सूची कहां देंगे। इसलिये चुप हो गये। हरिजनों को क्या मिला ? जमीनों की बात आ गयी। 13 लाख का आवंटन हुआ। हरिजन कब्जा लेने गया तो जम कर उसकी पिटायी हुई। 2½ हजार मोटरे चलती हैं तो क्या एक भी हरिजन को मोटर का परमिट मिला ? मिला हो तो बता दीजिये। दस हजार भरतपुर में ट्रेक्टर हैं। एक भी नाई, बलाई, हरिजन और किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ट्रेक्टर दिया हो तो बता दीजिये। 25 वर्ष में किसी को मिला शराब का ठेका, किसी को किसी चीज का ठेका मिला, किसी को बस का परमिट मिल गया और हरिजनों को मिला तिरंगा झंडा उसको लेकर जगजीवनरामजी के चरण छुओ। 25 करोड इनके कल्याण के लिये खर्च करते हैं। नीचे के तबके को ऊपर लाये क्या ? लेकिन यही प्रक्रिया दिखाई देती हैं कि बड़े आदमियों को आगे बढाया। छोटे को आगे बढाने के लिये 1 पैसा खर्च करें और 99 पैसे बड़े को बड़ा बनाने में खर्च करें तो छोटों का कैसे सुधार हो सकता है ? पांचवी योजना में भी यही हाल रहा है और यदि केन्द्रीय नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो 25 परसेन्ट हरिजन भूख से मर जावेंगे।

आज जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस से सरकार के कार्यकलापों का कोई तारतम्य नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि को रोक देने का काम भी इस सरकार के बूते में नहीं है।

अब सरकार ने हरिजनों को कहां किसको किस तरह की जमीनें दी हैं यह भी मैं बताता हूं। हरिदेवजी ने जमीनें ली हैं, सुखाड़ियाजी ने ली हैं। जयपुर के आसपास अनेकानेक राजनेताओं ने जमीनें ली हैं क्योंकि वे सभी परम्परा से खेती करते आये हैं।

अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो जिस तरह से देश में शरणार्थी आये और थोड़े से समय में ही उनको सब जगह बसा दिया। आज उनकी यहां के मूल निवासियों से बढ़िया हालत है। उसी तरह से यह सरकार इन हरिजनों को भी बसा सकती थी। अच्छी जमीनें दे सकती थी। पांच हजार वर्षों से यह शोषित वर्ग चला आ रहा है। इनका कल्याण नहीं हुआ। शरणार्थियों को बसा दिया, पर आज ये भूमिहीन के भूमिहीन हैं। इनकी एवज में जमीनें ली हैं हरिदेवजी ने, सुखाड़ियाजी ने और अनेकानेक राजनेताओं ने, राज्य अधिकारियों ने और बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारियों ने। तो मैं पूछता हूं इस सरकार की कोई नीति भी है।

ये तेंदू के पत्तों के जंगलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। इसके माध्यम से ये क्या करने जा रहे हैं ? प्राइवेट ठेकेदारों को

(श्री रामकिशन)
समाप्त करना चाह रहे हैं। पर राष्ट्रीयकरण का नाम केवल रहता है, इसके पीछे वही ठेकेदार मौज करते हैं। आज और सब प्रतिक्रियावादी हो गये हैं। केवल मात्र कांग्रेस ही प्रगतिशील रह गई है। आज राष्ट्रीयकरण के नाम से और समाजवाद के नाम से जो और जिस तरह के कारनामे ये कर रहे हैं उससे तो यह लगता है इस कांग्रेस सरकार की यह नीति है कि इस समाजवाद के नाम को और राष्ट्रीयकरण के इस तरह से बदनाम कर दिया जाय कि आगे आनेवाली सरकार के लिये इसके लिये कुछ करना असम्भव हो जाय। आप बताइये सरकार का इस्पात उद्योग चला। किसी कारखानेदार ने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट नहीं ली। जब स्टील की कीमतें बढ़ी तो इसकी मांग टाटा ने नहीं की। सरकारी उद्योग में चूंकि घाटा था इसलिये उसकी पूर्ति के लिये स्टील की कीमतें बढ़ाई गई। इसमें घाटा इसलिये था कि इन उद्योगों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और बेईमानी थी। स्टील की कीमतें इस सरकार ने बढ़ाई और इसके कारण दो साल पहले टाटा को 5।। करोड़ को फायदा हो गया।

इसी तरह से राष्ट्रीयकरण की बड़ी डोंग हांकते हैं। राष्ट्रीयकरण पर अनाप शनाप खर्चा करते है और कहते हैं हमने बड़े भारी प्रगतिशील कदम उठाये हैं। लाभ उसका प्रकारान्तर से होता है टाटा को। आज की मिसाल देना चाहूंगा। वन विभाग में स्टेट ट्रेडिंग शुरू किया गया। इसलिये किया गया कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, उपभोक्ताओं को सही कीमत पर कोयला लकड़ी मिल जाना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं वन मन्त्रीजी कि इसमें आप कहां तक सफल हुए हैं। इसमें किस के स्वार्थ की पूर्ति हुई है, उपभोक्ता के स्वार्थ की कि आपके उन्हीं ठेकेदारों की? आप जांच कराएं। ये वन विभाग के आपके अधिकारी सारा काम आज भी उन्हीं ठेकेदारों को देते हैं। लकड़ी कटाई से लेकर कोयला बनाई तक। फिर क्या राष्ट्रीयकरण हो गया? यह बेकार हो गया कि पहले जिन श्रमिक सहकारी समितियों के लोग इसमें लगे हुए थे वे बेकार हो गये। आपने आज टेण्डर लेने की प्रथा को चालू रखा है। ऐसा एक टेण्डर मेरे पास है। यह टेन्डर वन विभाग के द्वारा 1.8.69 को दिया गया और जिसमें कटाई का टेण्डर है। मेरा प्रसंग इसको रखने का नहीं था। पर आपके खोखलेपन को आपके गलत नारों को बताने के लिये इसे ले आया हूं।

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री) किसका टेण्डर है?

श्री रामकिशन : आपके विभाग का कटाई के लिये टेण्डर है यह?

श्री परसराम मदेरणा : हो नहीं सकता।

श्री रामकिशन : है। हो नहीं सकने का क्या प्रश्न है? यह तो तथ्य है। आपको भ्रम है क्या कि मैं जाली बनाकर लाया हूं?

श्री परसराम मदेरणा : बिलकुल।

श्री रामकिशन : मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं। आप अच्छी तरह से देख

Page No 30

(30)

(श्री रामकिशन)

लें। अपने वन विभाग के एक एक कर्मचारी और अधिकारी को दिखा लें। यह कटाई का टेण्डर है।

(श्री राम किशन ने लकड़ी की कटाई सम्बन्धी वन विभाग का टेन्डर सदन पटल पर रखा।)

श्री परसराम मदेरणा : वह कमीशन एजेण्ड का होगा। होगा तो फिर छोटे मामलों का होगा। बड़ी प्रोड्यूस का नहीं होगा, छोटी का होगा फिर।

श्री रामकिशन : छोटे का है या बड़े का है, किसका है, यह आप देख लीजियेगा। मैंने सदन की मेज पर रख दिया है। इसके बाद विवाद समाप्त हो जाता है। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, इन्हीं ठेकेदारों के लिये राष्ट्रीयकरण की आड़ में ये धन्धा चला रहे हैं। पहले ठेकेदारों में ही श्रमिक सहकारी समिति काम करती थी। उसे समाप्त कर दिया। वह हरिजनों की थी। हो सकता है कि उसमें सवर्ण वर्ग वाले भी हों। सरकार का काम था कि वह छोटे छोटे मजदूरों से सीधे काम करवाती। पर जो काम होता है वह इन ठेकेदारों को दे देता है विभाग और उन्हीं से सब काम करवा कर बेचने का काम कुछ अपने हाथ में रख लिया है। उसमें भी दफ्तरशाही और नोकरशाही की पूरी धांधलीबाजी चलती है। सरकार ने जैसा ख्याल है जो पहले 9 रुपया क्विन्टल बेचा था वह 25 रुपया कर दिया और वही भाव बढते बढते आज 60/64 तक चला गया है। अब इस तरह से शोषण बढ़ा या घटा। श्रमिक की आमदनी घटी या बढ़ी। उसका शोषण रुका या बढ़ा। एक एक ठेकेदार ने इस वन विभाग से अनाप शनाप पैसा कमाया है और भयंकर भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। अधिकारियों ने इन ठेकेदारों से मिलकर अपना घर बनाया है। अपनी जेबें भरी हैं।

तेंदू के ठेके की भी यही हालत है। इस तेंदू के ठेके ने तो बड़े बड़े मुख्य मंत्रियों को कुर्सियों को हिलाया है। मुख्यमन्त्रियों को हटाया है। पांच मुख्यमंत्री ये तेंन्दू के पत्र ले गये उड़ीसा में। वहां उस तरह का बड़ा धंधा यह है भी नहीं। छोटा सा है। पर यहां आन्दोलन नहीं होता। राजस्थान कमजोर है। सरकारी भ्रष्टाचार को सीमित नहीं किया गया, रोका नहीं गया तो फिर यहां भी यह रुकेगा नहीं, और इस तरह से आपका राष्ट्रीयकरण का सम्पूर्ण उद्देश्य ही फेल हो जावेगा।

आखिर हम कोई कदम उठाते हैं तो उसका कोई सामाजिक लक्ष्य होता है उद्देश्य होता है। पर इस सरकार का कोई लक्ष्य नही है। मेरे पास बहुत मामले हैं वन विभाग के। पर अधिक नहीं कहूंगा। समय थोड़ा है। आशा है वन मंत्रीजी इनकी जांच के लिये ही पूरे कदम उटावेंगे। पर मैं पूछता हूँ सरकार को ऐसी कोई मंशा भी है क्या कि समाजवाद को देश में लाया जाय। समाजवाद के नाम पर दुनिया के सबसे ज्यादा बदनाम पूंजीवादी लोग आज यहां पनप रहे हैं। आज ये लोग चाहते हैं कि समाजवाद के नाम पर ऐसे कदम उठाये जावें कि समाजवाद हमेशा के लिये इस देश से समाप्त हो जावे। समाजवाद बदनाम हो जावे। आज यह हालत है।

(श्री रामकिशन)

विश्नोईजी बोल रहे थे कि वे यू. पी. में जीत गये। हम तो पिट कर आये हैं। मान रहे हैं। पर क्या आप जीत गये? आप जीतने का मतलब क्या लगाते हैं? आपके वोट सारे घट गये। आप कहां जीत गये? वोट कम, सीटें कम और वोटर कम। जिन वोटरों के वोट आपको मिले हैं वे भी हम जानते हैं किनके वोटों के सहारे आप जीत गये हैं किसी तरह वहां यू. पी. में। हिन्दुस्तान में तीन जातियां रही हैं परम्परा से। जिनके बलबूते पर यह कांग्रेस अब तक जीतती आई है। वे हैं हरिजन, मुसलमान और ब्राह्मण। चुनावों को लेकर जितना जातिवाद कांग्रेस ने इस देश में फैलाया है उतना और किसी ने भी नहीं। अब ब्राह्मण तो रहे हैं जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा, हरिदेव जोशी ब्राह्मण, बहुगुणा ब्राह्मण। जातिवाद के नाम पर अपने नारे लगाये, टिकट बांटे। कांग्रेसी ब्राह्मणों में मुख्य मंत्री भी हैं। कांग्रेस आज जाति बिरादरी की पार्टी है। मुसलमान को डरा धमका कर आपने कांग्रेस को वोट देने के लिये मजबूर किया। आपने यहां तक कहा है कि अगर मुसलमान ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ये जनसंघ वाले उनकी गरदन काट देंगे। और फिर हरिजन। वे केवल जगजीवनराम के नाम पर वोट दे गये। आप इन वोटों का विश्लेषण करके देख लीजिये। इन तीन के अलावा अगर किसी और ने वोट दिये भी हैं आपको तो वे हैं चोर बाजार करने वाले, भ्रष्टाचारी, आपके परमिटों पर जीने वाले। ठीक है। हम पराजित हो गये। हम राज करने के भी अधिकारी नहीं है। पर आप किस बात पर खुश हो रहे हैं? मैं तो यह पूछ रहा हूं। मैं कांग्रेस वालों से निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके साथ हिन्दुस्तान का सबसे शोषित वर्ग रह गया है। और आदमियों का समर्थन आपको रहा नहीं। आप चाहें तो आज भी काफी काम कर सकते हैं। बड़े क्रान्तिकारी कदम आप उठा सकते हैं। सम्पत्ति और जमीन का बटवारा आप आज आसानी से कर सकते हैं।

मुझे ताज्जुब है आज इतनी कठिनाइयां होते हुए भी हिन्दुस्तान में आज बगावत क्यों नहीं होती। कारण एक ही है। हम लोग कमजोर हैं।

मैं पूछता हूं आज आप समाज को क्या दे रहे हैं। दूसरे देशों में क्रान्तियां हो रही हैं। बड़े बड़े पूंजीपति समाप्त हो रहे हैं। पर हिन्दुस्तान में आज पूंजीवाद पनप क्यों रहा है, भ्रष्टतन्त्र चल क्यों रहा है। इसकी विवेचना करनी होगी।

मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा। कांग्रेस की स्थिति देश में क्या है? आज उसकी स्थिति देखकर मुझे न दर्द है, न गुस्सा है, न खुशी है न गम है। पर एक चीज कहना चाहूंगा। भरतपुर का चुनाव हुआ। मैं जीत गया वहां। कांग्रेस हार गई। मैं हार भी सकता था। मैं वैर क्षेत्र में उषा जैसी विधायिका से हार गया जिसका राजनीति से सम्पर्क नहीं था। मैं उनकी शान में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो ठीक नहीं हो। क्योंकि वे महिला हैं और मैं महिलाओं का बड़ा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री रामकिशन)
हिन्दुस्तान के वोट ने मुझे उपाजो के मार्फत हरा दिया।

एक माननीय सदस्य : जमानत भी जब्त हो गई।

श्री रामकिशन : कांग्रेस के लोगों ने भरतपुर में चुनाव लड़ा। मैं पूछता हूं आप किसलिये यह चुनाव लड़ रहे थे? क्या सामाजिक मान्यताएं थीं? मेरे अकेले के जीतने से और आपके उम्मीदवार के अकेले के वहां से जीत जाने से आपका राज तो जाने वाला नहीं था। आपका अत्यधिक बहुमत था। फिर दो चार साम्यवादी आपको पीठ पर हैं। फिर आपने भरतपुर के चुनाव में गलत मर्यादाएं क्यों कायम कीं? लोकतन्त्र की भावनाओं को उसकी सही मर्यादाओं को क्यों तोड़ा? आप जानते हैं आपने वहां किस तरह से चुनाव लड़ा? कमला जी, आप ही बताइये आप वहां थीं, आपके पास कितनी जीपें थीं। बता सकती हैं आप? कितना साहित्य था बांटने के लिये आपके पास? दस हजार का मापदण्ड आप किस तरह से निभा रही थीं वहां? जब हम ऐसा करेंगे तो किस तरह से समाजवाद की बात निभा सकेंगे?

भ्रष्ट व्यापारियों से कैसे निपट सकेंगे? कैसे आप उनसे लड़ सकेंगे? महंगाई और अभाव की स्थिति से कैसे मोर्चा ले सकेंगे? आप एक छोटे से चुनाव में बीस लाख खर्च करें। और यह पैसा उन चोर बाजारियों से लेकर आप उनसे कैसे लड सकेंगे?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास तो एक ही जीप थी।

श्री रामकिशन : आप जैसे मिनिस्टर और भी थे, उनके पास कितनी थी, आप के कार्यकर्त्ताओं के पास कितनी थी, कुल कितनी थी, आप बता दीजिये मैं समझता हूं आप झूठ नहीं बोलेंगी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे पूछता हूं आपने दस हजार से अधिक खर्चा नहीं किया?

श्री रामकिशन : मैं बताऊंगा आप को यह सब। मेरे में साहस है। साहस तो उनमें नहीं हो सकता जो जमाखोरीबाजों, चोर बाजारियों और भ्रष्ट व्यापारियों से पैसा लेता हो।

श्री दीपंकर : जितनी बड़ी पार्टी होती है, उतनी ही बड़ी फौज उसके पास अपने कार्यकर्त्ताओं की होती है और वे जाते हैं वहां। उतनी ही जीपें होती हैं।

श्री रामकिशन : आगे चल कर वहां मुख्य मन्त्री जी एक बयान देते हैं एक वहां कि विधान सभा में अगर रामकिशन पहुंच गया तो एक गाली देने वाला वहां पहुंच जावेगा। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है? विधान सभा का मेरा पूर्व का सारा रिकार्ड देखकर कही भी आप बता सकते हैं कि मैंने, किसी को गाली दी हो या कभी। फिर गाली देने वाला कहकर क्या आपने मेरा अपमान नहीं किया? मैं गाली देता हूं? लोकतन्त्र की जितनी सेवा हमने की है, शायद मुख्य मन्त्री ने अपने जीवन काल में नहीं की है। आपकी स्थिति क्या है? जब गिरि के लिए वोट पड़ रहे थे तब आप सिंडीकेटी थे। केवल चार थे वे भी घर से बाहर नहीं गये, घर के अन्दर ही

Page No 33

(33)

(श्री रामकिशन)

बैठे रहे। शिव चरण जी किसी तरह खुशामद करके आ गये बाकी बाहर ही बैठे रहे। मुख्य मन्त्रीजी ने इन्दिरा गान्धी के खिलाफ बात लिखी थी लेकिन सरकार उनकी बन गई तो रातों रात उनके चरण सेवक बन गये। दूसरों में साहस नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब है आप वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर रामकिशन को विधान सभा में जिता दिया तो अनर्थ हो जायेगा, वे विधान सभा में गाली देंगे। मेरे समझ में नहीं आया उद्देश्य क्या था इनका? इतना भंयकर प्रचार हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ।

मैं आपको एक और जानकारी देता हूं श्री हरिदेवजी जोशी, राजस्थान के मुख्य मंत्री भरतपुर में पहुंचते हैं और हमारे यहां के एक प्रधान हैं श्री होती लालजी पारासर, वे मेरे भी सम्बन्धी होते हैं। उनके घर पर ब्राह्मणों की एक मीटिंग बुलाई। केवल ब्राह्मणों की मीटिंग उनके यहां बुलाकर यह कहा गया कि यदि रामकिशन जीत जायगा तो मुख्य मन्त्री का अपमान हो जायेगा इसलिए ब्राह्मणों तुम सोचो। उपाध्यक्ष महोदय आपको ताज्जुब होगा वहां पर कमला जी को ही क्यों लगाया गया, राम नारायण चौधरी जी को ही वहां क्यों लगाया गया क्यों नहीं खेतसिंह जी को वहां लगाया गया, शिवचरण जी को क्यों नहीं लगाया गया, क्या ये योग्य नहीं थे? चन्दनमलजी को वहां नहीं लगाया गया। क्या, उपाध्यक्ष महोदय, इनको भाषण देना नहीं आता था? क्या ये किसी प्रकार चुनाव प्रचार के लिए अयोग्य थे? लेकिन इसके पीछे कारण यह था कि उस इलाके में जाट वोटर थे इसलिये रामनारायणजी चौधरी को लगाया गया, कमला जी को लगाया गया···

श्री दीपंकर : आपके समर्थन में चौधरी चरणसिंह जी कैसे आये?

श्री रामकिशन : आपको जानकारी नहीं है, आप तो बैठे रहो।

तो मैं निवेदन कर रहा था राम नारायण जी और कमला जी भी मेरे मित्र हैं। बहुत अच्छा है लोकतन्त्र में यह सब चलता है। इसके अलावा चन्दनमल जी वहां क्यों नहीं पहुंचे क्योंकि वहां कोई ओसवाल नहीं था। खेतसिंह जी को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां कोई राजपूत नहीं थे। चुनाव में हार-जीत कोई मायने नहीं रखती है। मैं हार भी जाता तो कोई बात नहीं थी और उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उधर एक बस्ती में 100–125 घर मुसलमानों के हैं वहां श्रीमती ऊषी खां को भेज दिया इसी तरह हमारे यहां कुछ टीचर्स हैं तो पंचायत समिति में जो टीचर्स का चयन करते हैं, श्री वासवानी को भेज दिया। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को लगा दिया गया। हमारे गांव में यादवों के भी पांच–सात घर हैं उनके वोट तोड़ने के लिये श्रीमान् यादव साहब को भेज दिया गया। अब आप कहेंगे शिव चरण जी को भेजा गया, इसकी भी एक कहानी है। इनके और श्री गिरधारी लाल जी के मतभेद हैं। अब अगर ये वहां पहुंच जाते तो शायद कुछ नुकसान हो जाता···

श्री शिवचरण माथुर : यह बिल्कुल गलत है।

श्री रामकिशन : आप धीरज रखिये।

श्री दीपंकर : हमारे जितने कार्यकर्ता थे पहुंच गये। यह आप क्या कहना चाहते हैं···(व्यवधान : अश्रव्य)···आप जैसे व्यक्ति धन्यबाद प्रस्ताव पर बोलते··· (अश्रव्य) ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं थी। आप कैसे जीतकर आ गये··· (व्यवधान : अश्रव्य)···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दीपंकर : ब्राह्मणवाद और ये क्या क्या···

श्री रामकिशन : सुनिये, आप राजनीति में नये हैं। आपको राजनीति में दर्द नहीं हो सकता है। हार जीत तो···

श्री दीपंकर : हम कितने अर्से से हैं, यह आपको पता ही नहीं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, माननीय शिव चरण जी क्यों गये ? दूसरे एक कायस्थ थे, जो आपके रिश्तेदार थे उनके आपकी वजह से वोट टूट गये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं खेत सिंह जी को क्यों नहीं भेजा ? माननीय बिश्नोई जी को क्यों नहीं भेजा ? माननीय चन्दन मल जी को क्यों नहीं भेजा क्योंकि उनके घर नहीं थे। वहां कोई राजपूत और ओसवाल नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कांग्रेस के इस पतन पर बड़ा दुःख और अफसोस होता है। कांग्रेस के कार्यक्रम क्या है ? और उससे अगर हम चुनाव परिणाम में हार भी जायं तो कोई बहुत बड़ी हार जीत तो थी नहीं। पिछले चुनाव परिणामों को बताया गया और एक हमारे यहां बिधायिका हैं, श्रीमती ऊषा प्रकाश इनको जगह जगह घुमाया गया, और कहा गया, इन्होंने राम किशन को गत चुनावों में हरा दिया। अब मैं जीतने हारने की बात नहीं कह रहा हूं। खूब प्रचार किया गया राम किशन को हराने वाली श्रीमती ऊषा प्रकाश और उषाजी यह कहें कि मैंने औरत होकर हरा दिया तो तुम तो पुरुष हो। हार गये बहुत बढ़िया लेकिन औरत ने हरा दिया इसलिये कि नारी हीन है। यह कांग्रेस ने जगह जगह प्रचार किया और जगह जगह पर इनको घुमाया। उपाध्यक्ष महोदय, केवल नारी की हैसियत से घुमाया गया कोई बहुत बड़ा वक्ता की हैसियत से नहीं घुमाया गया ताकि पुरुष में ताकत आ जाय। लेकिन हमारा तो यह कहना है कि हम तो नारी से हमेशा पराजित हुये हैं। मेरे दल के श्री माणकचन्द जी श्रीमती कान्ता कथूरिया से हार गये थे। हम तो नर नारी के समर्थक रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उस चुनाव में बिन्दियां बांटी जाती हैं। मेरा कोई सुधार से मतलब नहीं है–यह गाय बछड़े वाली बिन्दियां और केवल यह बताने के लिये कि यह सुहाग का चिन्ह है तो फिर बहुत सी औरतें बिन्दियां नहीं लगाती हैं तो क्या वे सुहागिन नहीं। जो नारी बिन्दी नहीं लगाती है तो यह उनके लिये

(श्री रामकिशन)

एक अपमान है। अगर यह बिन्दिया लगाकर ही सुहाग की निशानी मानी जाती है, तो फिर पुरुषों के लिये भी कोई निशानी देखनी पड़ेगी। कहीं कम्बल बांटे जा रहे हैं और कहीं कुछ किया जा रहा है। मुझे चुनाव की हार जीत से कोई मतलब नहीं। लोकतन्त्र में हारते और जीतते हैं, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वह स्वस्थ परम्परा का न होकर निकृष्ट तरीके का ही कहा जा सकता है। एक हमारे माननीय मंत्री महोदय मुंशी लाल जी ये नये नये तो मंत्री बने, इनको भी कमला जी के साथ लगा दिया। पहले इन्होंने लोक सभा की सीट के लिये टिकट मांगा था, बेचारे चले आये। मैं समझना चाहता हूं आप किस उद्देश्य से चले आये ? मैं कोई ज्यादा शिकायत नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस दल का इलाज अब असम्भव है, दुनियां की कोई दवा इनका इलाज नहीं कर सकती है। आज इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। इनका आचरण पूंजीपति का है, व्यवहार अफसरशाही का है और जहां जिस तरह का अवसर होता है, वैसा ही ये आचरण करने लग जाते है। स्वयं का कोई आचरण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मिसाल के तौर पर भी आप एक ऐसा उदाहरण बता दें कि मैंने किसी अफसर या किसी सरकारी कर्मचारी को कहा हो कि मुझे वोट दीजिये, बल्कि जिला परिषदों के भी किसी कर्मचारी को कहा हो कि मुझे वोट दीजिये। आप यह मिसाल दीजिये मैं सदन से नहीं, राजनीति से हटने को तैयार हूं...

श्री दीपंकर : ...(व्यवधान अश्रव्य)

श्री राम किशन : एक घण्टे का टाइम है...

(व्यवधान अश्रव्य)

एक घण्टे मेरे दल का टाइम हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। चुनाव में जीतना हारना मेरे लिये ज्यादा महत्व का नहीं है और अब कोई लेना देना भी नहीं है। जिन व्यवस्थाओं पर हम संघर्ष कर रहे हैं, आपने समाजवाद को अपना धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिये मेरे संस्कार आपसे मिल गये इसलिये मैं चाहूंगा, आप का आचरण भी उसी के अनुरूप हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनाव का थोड़ा सा प्रसंग इसलिये लाया हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य सोच लें।

अब राजस्थान के निर्माण के सम्बन्ध का प्रश्न आता है...

श्री विजय सिंह : Most boring.

श्री जेठ मल बरवड : .... (व्यवधान अश्रव्य)

श्री राम किशन : माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य को जाने की जल्दी हो तो चले जायं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो स्थिति हैं वह ऐसी बनती जा रही है। हमारे राजस्थान के निर्माण का सवाल है इसमें भी

(श्री रामकिशन)
सभी माननीय सदस्यों को एक तरह से सोचने का आदी होना चाहिए। मुझे उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ सुझाव देने हैं।

सीलिंग के संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, बारबार चर्चायें होती रहती हैं। सीलिंग का कानून कभी नहीं आयेगा, और क्या जो बिना जमीनों के लोग हैं उन को जमीन मिलेगी? अगर आज सरकार समाजवादी हो गई है तो क्या आप एक बोर्ड का गठन करेंगे और 20 साल से पहले पहले जिन लोगों ने जमीनों को बेचा है, जिन लोगों के पास जमीन थी और दूसरे लोगों के नाम कर दी है क्या उनसे जमीन वापिस लेने के लिए सरकार तैयार है? अगर तैयार है तो इस सीलिंग कानून का अर्थ हो सकता है। अगर नहीं लेने को तैयार है तो जो नयी धारायें लाई जा रही हैं, उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा 40 हजार एकड़ जमीन निकलेगी और उसमें से भी अच्छी जमीन बहुत कम होगी, और ज्यादातर ऐसी होगी जो कि बिना खेती की होगी या गड्डे वाली होगी। आखिर इस समाज का हम क्या निर्माण करना चाहते हैं। हमें इस बात को सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बातों के बारे में सरकार से कहना चाहूंगा कि आज गांवों में नयी समस्यायें पैदा हो रही हैं। खाद आपको मिलने वाला नहीं है, अनाज आपको मिलने वाला नहीं है। हां, तेल के संकट से हम आपके साथ हैं। तेल के बारे में जो आपका विश्लेषण है और हमारा विश्लेषण है उसमें 15 परसेंट से ज्यादा फर्क नहीं है। आज खाद की मांग बढ़ रही है और नये उपकरणों को काश्तकार अपनाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आज हमारी पंचायती राज संस्थायें हैं उनका कोई उपयोग है? अगर कोई उपयोग नहीं है तो फिर आप एक कार्यक्रम बनायें। आगामी साल से जब खाद नहीं मिलेगी, विदेशों से तेल पदार्थ आपको पहले ही कम मिल रहे हैं तो हमें देशी खाद का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हुए तो बढ़ती हुई आबादी का संकट इतना व्यापक हो जायेगा कि आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां दो तरह के काम हैं–एक तो मल्टी परपज रीवर स्कीम जिसमें कि बिजली पैदा हो रही है और साथ ही साथ में सिंचाई भी हो रही है। इस सम्बन्ध में आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकासशील देश होते हैं वह अधिक लाभ के कामों को पहले करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज आपकी माईनर स्कीम का जिक्र आता है। यह केवल एक क्षेत्र के लिए माईनर स्कीम रखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में हर साल बाढ़ आती है क्या यह बाढ़ नहीं रुक सकती? भरतपुर में जो बाढ़ आती है वह केवल गम्भीरी नदी से आती है, जो गम्भीरी नदी करौली के पास से निकलती है और बयाना के पास जाकर खत्म हो जाती है। जब इस नदी की बाढ़ आती है तो करोड़ों

(श्री रामकिशन)

की सम्पत्ति को बरबाद कर देती है। जब अमेरिका के लोग चन्द्रमा पर पहुँच गये तो क्या हमारे यहां इस नदी का भी इन्तजाम नहीं हो सकता? वैसे चुनावों में लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है, चुनावों में भरतपुर में इरिगेशन के डाक बंगले में इसके लिए इन्तजाम हुआ और जिसमें लाखों रुपये की गड़बड़ें हुई हैं और गलत पेमेंट हुए हैं। जब सरकार माईनर स्कीम बना रही है तो सबसे पहले बाढ़ नियन्त्रण के काम की ओर ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, जब चीन आजाद हुआ तो उसने सबसे पहले यांगसी नदी का इन्तजाम किया और सात साल के प्रयत्नों के बाद उस नदी को बांध दिया गया। दूसरी ओर, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की हालत यह है कि हम जितना पैदा कर रहे हैं उतना ही बाढ़ में समाप्त हो जाता है। राजस्थान में केवल दो जगहों पर ही बाढ़ आती है एक तो गंगानगर में और दूसरे भरतपुर में। यदि आप बाढ़ नियन्त्रण का इन्तजाम नहीं कर सकते तो आप राष्ट्रीय सम्पत्ति को कैसे बढ़ायेंगे। हमारी राष्ट्रीय सम्पदा जो हम बढ़ाते हैं वह सारी नष्ट हो जाती है।

एक जानकारी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं और देना चाहूंगा। भरतपुर में दसियों बार बाढ़ आई जब से कांग्रेस ने राज्य करना शुरू किया और पहले सौ वर्षों में केवल तीन बार ही आई। इसका कारण क्या है? क्या इन्द्र की बदली हो गयी है कांग्रेस के राज्य में? असल में कारण यह है कि राजाओं का राज्य पचासों तरह से खराब था–सामन्ती प्रथा, शोषण और एक पक्षीय दृष्टिकोण–वह सब बुराइयां उस जमाने की हैं लेकिन मैं आपको कह दूं कि उस समय में भ्रष्टाचार कम था और जो लोग भ्रष्टाचारी थे और गलत काम करने वाले थे उनको सजा मिलती थी। भरतपुर में दसियों बार बाढ़ आ चुकी है जब कि यह कम आनी चाहिये क्योंकि अब तो दसियों जगह पर बांध बंध गये हैं और उस समय बांध नहीं थे फिर भी उस जमाने में इतनी बाढ़ नहीं आती थी। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि सरकार केवल मौखिक व्यवस्था नहीं करे। और आपके मन में राजस्थान निर्माण की तमन्ना है तो ईमानदारी से इस बात के लिए कोशिश करें। चुनावों के दिनों में मुख्य मंत्री जी कह आये कि जहां से कांग्रेस नहीं जीतेगी वहां पर विकास के काम नहीं होंगे। मत करायें वहां पर विकास के काम लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि गंगानगर का विकास नहीं हुआ, और भरतपुर का विकास नहीं हुआ, और सवाई माधोपुर का विकास नहीं हुआ तो आप निश्चित समझिये कि राजस्थान आपके लिए अनाज नहीं दे सकता। मैंने यहां पर सारे आंकड़े छोड़े हैं क्योंकि सुमित्रा जी ने इस सम्बन्ध में सदन को काफी जानकारी दी है। मैं एक जानकारी चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा इस पंचम पंचवर्षीय योजना का, जो मौजूदा प्रारूप है उसका, नये ढंग से अध्ययन करेगी? मैंने सुना है कि राजस्थान में कोई योजना बोर्ड का गठन किया गया है। उन सम्भावनाओं को आज से मिलायें। कुछ मुल्कों ने तो रास्ता अपनाया है चाहे वह इजराइल हो, चाहे सूडान हो हमारी हालत करीब करीब उनकी तरह की है। मैं नहीं चाहता हम उनके प्रयोगों की नकल करें लेकिन

Page No 38

(38)

(श्री रामकिशन)

हमारे राजस्थान के योजना बोर्ड को, उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए और सुझावों के साथ योजना आयोग को सुझाव पेश करने चाहिये।

भरतपुर में पशुपालन के लिए बजट रखते हैं उसकी क्या कीमत है? भरतपुर में ज्यादा जरूरत है बिजली की, भरतपुर में ज्यादा जरूरत है पानी की। राजस्थान के अन्दर एक हिस्से में पशुधन को बढ़ाने की जरूरत है लेकिन हमारा पेटर्न एक ही है। एक ही पंचायत समिति का पेटर्न है—उतना ही बजट तो बाड़मेर के लिए और उतना ही भरतपुर के लिए। उतना ही इरिगेशन के लिए छोटे टैंकों के लिए भरतपुर में प्रावधान है। तो उतना ही बाड़मेर और उतना ही जैसलमेर के लिए है। आखिर हम सभी स्थानों की सम्भावनाओं को भी देखें। आपको विकास किसी क्षेत्र का नहीं करना है तो ना करें, आप मालिक हैं। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो राजस्थान का भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप पेटर्न को चेन्ज करें। इसके अलावा हमें ऐसे उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए जो कि नेशनल इन्कम के हिस्से हों। सारे देश में उद्योगों की मार्फत नेशनल इन्कम का 12 पर्सेन्ट मिलता है और हमारे राज्य को 4 पर्सेन्ट से भी कम मिलता है और वह भी संगठित उद्योगों से मिल रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र की समस्यायें हैं। जन संख्या ज्यादा हैं और पूंजी कम है। टेक्नीकल नालेज बहुत कम है इसलिए ऐसे उद्योगों को चालू करना चाहिए जो कि कम पूंजी के हों और यहां के उपलब्ध माल से ही इन्डस्ट्रीज चल सकें। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी कई बार कई यूरोपीय देशों की चर्चा करते हैं और इसलिए करते हैं कि वह साल डेढ़ साल में वहां घूम आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन समाजों का निर्माण किया है और जिम्मेदारियां डाली हैं। रूस का कृषि मंत्री क्यों हटा दिया गया? कृषि के क्षेत्र में कुछ कमियां रहीं और उनकी जिम्मेदारी थी इसलिए उनको वहां से हटाना पड़ा। क्या आपकी सरकार किसी भी तरह से किसी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है? जब मंत्री जिम्मेदारी लेंगे तो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट जिम्मेदारी लेंगे तो ग्राम सेवक जिम्मेदारी लेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हर मंत्री को उनके विभाग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाये। मैं रूसी प्रणाली का समर्थक नहीं हूं लेकिन हटाने वाली प्रणाली का मैं समर्थन करता हूं। जिस विभाग के रिजल्ट्स नहीं आयें तो उस विभाग के मंत्री को हटा देना चाहिए। जब तक इन मान्यताओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक विभागाध्यक्ष जिम्मेदारी से नहीं रह सकते। लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं और आप दिल्ली और अहमदाबाद जाते हैं तो मालूम होता है कि कंगाली नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ भी कह सकने के लिए जगह नहीं मिलेगी जो पूंजी रोकने के लिए होनी चाहिए वह किसी पूंजीपति को नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए कह दिया जाता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई इसका जिक्र नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो यह सोशलिस्ट पार्टी कर रही है। यह नहीं

(श्री रामकिशन)

है । आज पार्टियां पीछे रह गई हैं, जनता आगे जा रही है । आप गुजरात में चले जायें । कहीं भी चले जायें । आज सारी जगह यही हो रहा है । वह हवा दूसरे इलाकों में भी जाकर पहुंची है । आज हम ऐसी जगह आकर खड़े हो गये हैं कि हमें कहां जाना है, आज यह हम हल नहीं कर सकते है । इजरायल में रेगिस्तान है । वहां के लोग क्या कर रहे हैं ? पांच साल के आंकड़े देख लें । इजराइल के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं । पैदावार भी बढ़ा रहे है । 10 करोड़ अरबों से 20 लाख इजराइल लड़ भी रहे हैं, पैदावार भी बढ़ा रहे हैं । इसी आधार पर वहां के एक मन्त्री ने इस्तीफा दिया है । अगर हम उनसे नहीं सीख सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आज सुरक्षा मंत्री ने शपथ ले ली है । आज वह हो गये हैं ।

श्री रामकिशन : वह सूचना मुझे नहीं है । गलती मुझे मानने में देर नहीं लगती है । आपको समझाने में लगती है ।

अन्त में बजट के मौके पर राजस्थान की तस्वीर रखना चाहूंगा । वह ऐसी भयंकर है मगर आपके दर्द का असर समाप्त हो गया है । निर्जीव पत्थर हो गये हैं । तुलसीदासजी ने कहा है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है । लेकिन आप पर असर होने वाला नहीं है । रिपब्लिकन पार्टी के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं । यह वह लोग हैं जिनके श्रम से महल बने हुए हैं । दिल्ली का सिंहासन बना हुआ है । उन नौजवानों के दर्द के साथ में हमें अपने को जोड़ना पड़ेगा । उनकी दो छोटीसी मांगें हैं । डा. अम्बेडकर को मान्यता दो और रविदास को मान्यता दो । आपने देखा है कि पिछले सौ साल में डा. अम्बेडकर जैसा आदमी नहीं हुआ है । रविदास 14 वीं सदी के सन्त थे । बंगाल के चण्डीदास भी 14 वीं सदी के सन्त थे । उन्होंने उस युग में ब्राह्मण होते हुए रामी धोबिन से शादी की थी । दुनियां में कहीं भी चले जाओ, या तो कृष्ण ने राधा के पैर दबाये हैं या चण्डीदास ने रामी धोबन के पांव दबाये हैं । उसे मां भी कहा, बहिन भी कहा, और गुरू भी कहा ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : हम तो देश सेवा में लगे हुए हैं । हमें साहित्य पढ़ने का अवकाश ही कहां है ।

श्री रामकिशन : हां, आप सेवा में लगे हुए हैं ।

मैं निवेदन कर रहा था, शिक्षा के मामले में कहा गया है । स्कूल खोलने के लिए कहा गया है । मेरा यह मानना है कि ये पब्लिक स्कूल असमानता के प्रतीक है । पब्लिक स्कूलों में 700 रुपये महीने एक लड़के पर खर्च हो रहा है । पब्लिक स्कूलों को बन्द करना आपके हाथ में है । पब्लिक स्कूलों में सेठों के, सेक्रेटरियों के, राजनैतिक नेताओं के और सामन्तों के लड़के पढ़ते हैं । हरिजनों और किसानों के लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं । इसी प्रकार से बेरोजगारों को वजीफा देने की घोषणा की गई है । वह तो अच्छी बात है । हम किसी सेठ या संपन्न लड़के की बात नहीं कर रहे हैं । जिनके पास काम करने का जरिया नहीं है, उन नौजवानों को या तो काम दो या बेरोजगारी का भत्ता देना पड़ेगा । इन कमियों के साथ में आप राजस्थान को तस्वीर बनाना चाहते हैं ।

(श्री रामकिशन)
आप टैक्स लगा देते हैं। मैं दो साल बाद सदन में आया हूं। यहां सदन के बाहर हिस्से बनाने की क्या जरूरत थी? बाड़मेर में पानी नहीं है। नव निर्माण मे मेहनत करनी पड़ती है। आप टैक्स लगाते हैं तो अपनी विलासिता के लिए लगाते हैं। वियतनाम के नेता डा. हो ची मिन्ह कहां रहते थे? मैं समझता हूं कि आप को इसकी जानकारी नहीं है। आप चर्चा करेंगे समाजवाद की रहेंगे महलों में। ऐसा विरोधाभास राजनीति में दुनियां मे कहीं नहीं देखा। कुछ माननीय सदस्यों को जाना है। मैंने आंकड़े दिये नही हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक भी लाइन ऐसी नहीं है, जिसके लिए धन्यवाद दें। मैं आशा करूंगा कि सदन इसको एक स्वर से अस्वीकार कर दे। इससे नई भावनायें जनता में जाग्रत होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनाज वसूल करने का काम उठाया है, उसमें बहुत ही कमी है। राजस्थान के पश्चिमी जिले जो बीकानेर आदि हैं, इन जिलों की एक अलग बात है। उनमें अकाल पड़ता आया है। यहां पर भूमि की जो उपज है, उसके हिसाब से सरकार ने लेवी नहीं लगाई है। कोटा और गंगानगर के जो इलाके हैं, वह सिंचित इलाके हैं। बीकानेर और चूरू बारानी इलाके हैं। वहां का आधार भी वही रखा है। उनका यह आधार सही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार का कोई सही आधार होना चाहिए। उपज के आधार पर लेवी होनी चाहिए। सरकार ने उपज के आधार पर लेवी नहीं लगा कर वसूली की है। कोटा, गंगानगर, भरतपुर और अलवर के जो इलाके हैं, वहां की जमीन एक साल में दो फसल देती है। बीकानेर और चूरू में जमीन की हैसियत देख कर राजस्थान सरकार ने नहीं लगायी है इसलिए मैं मांग करता हूं कि जमीन की हैसियत देख कर लेवी लगानी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जमीन की हैसियत देखकर पुनर्विचार करके लेवी लगायें।

दूसरे, उपाध्यक्षजी, आज के जमाने में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की नारेबाजी है, वहनारेबाजी बहुत सीमा पार कर गई है। सरकार की तरफ से भी यह बात कही जाय कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करेगी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का तो जिम्मा है, वह सरकार का है। यदि सरकार के नीचे रहने वाले अधिकारी या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिम्मेदारी राजनैतिक दूसरी पार्टी की नहीं है राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि उसके हाथ में राज्य की व्यवस्था है। अगर राजस्थान सरकार के मन्त्री यह घोषणा करें कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे तो यह बात गलत है। उनको भ्रष्टाचार खत्म करना है, वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में बैठने वाले मन्त्री गणों

Page No 41

(५१)

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

की। उनके खुद के डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जगह जगह बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस रूप में कर रहे हैं कि एक एम. एल. ए. है, उसके घर पर जाकर बड़े बड़े अधिकारी बैठ जाते हैं, उसके घर पर रोज हाजरी देते हैं। मैं मानता हूं कि इससे जनता के दिमाग पर असर पड़ता है और वह इसको भ्रष्टाचार बढ़ावे के रूप में मानते हैं। सुबह और शाम को एम. एल. ए. के घर पर चक्कर बड़े बड़े अधिकारी लगायें। मैं मानता हूं कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार इस तरह कर रहे हैं, और एम. एल. ए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिन एम. एल. ए. का कोई टेलीफोन जाय और उस एम. एल. ए. का काम हो जाय। दूसरे एम. एल. ए. कई चक्कर लगाये तब भी उनका काम नहीं हो। मैं इसको भ्रष्टाचार मानता हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो।

लेवी का जिक्र किया, किसान लेवी देंगे, लेकिन लेवी के अन्दर सफल तभी होंगे जब आप काश्तकारों को सहयोग देंगे। आज काश्तकार जो कुए लगाते हैं उनको बिजली नहीं दी जा रही है। अगर आपको अनाज की उपज बढ़ानी है तो आप कुओं को बिजली दें, अच्छा बीज दें, अच्छी खाद दें, ताकि काश्तकार, जो देश में अन्न की समस्या है, उसका समाधान कर सके।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से चाहूंगा पंचायतों के अन्दर रिजर्वेशन के बारे में। आपने सब जगह पर रिजर्वेशन रखा है, पार्लियामेंट में रखा है। विधान सभाओं में रखा है। मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में जो सरपंच हैं, उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों में भी रिजर्वेशन होना जरूरी है। इस सम्बन्ध में सरकार कदम उठा ले तो मैं समझूंगा कि कांग्रेस, सरकार और हरिजनों के लिए यह सबसे अच्छा कदम रहेगा। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार सरपचों में रिजर्वेशन जन संख्या के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर करे तो मैं बहुत ही अच्छा कदम इसको मानूंगा। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार कदम उठाये।

उपाध्यक्ष जी, बिजली के मामले में मैं चाहूंगा, सरकार गांवों के अन्दर पहले बिजली दे। सरकार की नीति है, बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों को इन्डस्ट्री लगाने के लिए बिजली देने की। सरकार के पास काश्तकारों को, गरीब जनता को बिजली देने के लिए बजट नहीं है। सरकार बजट की बात कह कर इसे टाल देती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि गांवों में अधिक बिजली पहुंचायी जाय।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि गांवों में पीने के पानी की समस्या है। आज पच्चीस साल की आजादी के बाद भी पीने का पानी गांवों में नहीं दे रहे हैं इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं चाहूंगा कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था सरकार को अच्छे ढंग से करनी चाहिए।

हरिजनों को भूमि देने के सम्बन्ध में आंकड़े तो बहुत दिये गये हैं, लेकिन आज तक

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

भी किसी हरिजन को भूमि नहीं दी गई है। बीकानेर के अन्दर छः हजार हरिजनों के मकान हैं, जो बीकानेर के अन्दर बहुत अर्से से आबाद हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक हरिजनों को उस भूमि के रिहायशी पट्टे नहीं दिये गये हैं। मैं मांग करता हूं कि आप इसकी जांच करें कि इन छः हजार हरिजनों को पट्टे क्यों नहीं दिये गये हैं। इसकी जांच करें और ऐसे बसने वाले हरिजनों को जल्दी ही पट्टे दिलाने की मेहरबानी करें।

उपाध्यक्ष जी, गांवों में, राजस्थान में बहुत सहकारी समितियां बुनकरों की हैं, हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी बहुत से लोगों की हैं। सहकारी समितियों में गरीब तबके के लोगों के अधिकारों का बड़े लोगों के भ्रष्टाचार के द्वारा हनन हो रहा है। लोगों के नाम से लोन ले लिया है और उनके नाम से आज कुर्कियां हो रही हैं। उदासर गांव भैसा में है, वहां पर हरिजन जाति के लोग हैं, उनके नाम से तकाबी उठा ली, उनके नाम से सोसाइटी से कर्ज ले लिया लेकिन अब उनकी वसूली की जा रही है। इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने न तकावी ली है न कोपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है। झूठे दस्तखत करके तस्दीक करके लोन ले लिया, अब उन बीस-पच्चीस काश्तकारों से वसूली की गई है।

मैं अधिक लम्बा भाषण न देकर केवल इतनी ही बात कह कर राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर जिले में लेवी लगाई गई है वह व्यवहारिक दृष्टि से नहीं लगाई गई है, ईर्ष्या के भाव से लगाई गई है। वहां एक फसली इलाका है और 9 साल से वहां अकाल है तब भी वही लेवी है और कोटा, गंगानगर में भी वही लेवी है। इसलिए इस पर सरकार पुनर्विचार करे। इस तरह से अकाल पीड़ित इलाकों में लेवी नहीं लगानी चाहिए। वैसे लेवी राष्ट्रीय हित में है और हमें लेवी देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में पधार कर जो अभिभाषण दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में फर्माया कि राज्य सरकार ने अकाल और बाढ़ से मुकाबला करने में किसी तरह की कसर नहीं रखी। मैं चाहता था, माननीय राज्यपाल महोदय इसके बजाय यह कहते कि राजस्थान की जनता ने अकाल और बाढ़ का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं रखी तो ज्यादा उपयुक्त होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ा गये साल में, वह ऐसा भयंकर अकाल था कि मैं समझता हूं कि जो हमारे देश में छप्पनिया अकाल के बारे में कहा करते हैं, वह अकाल भी इतना भयंकर नहीं था। इतने अकाल पड़ने के बाद में गये साल के अकाल ने लोगों की कमर तोड़ दी, लोगों को भूखा मार दिया होता। उसके बाद में बाढ़ आयो, उसने भी भयंकर रूप लिया। लेकिन जनता ने उसका भी मुका-

(श्री विजयसिंह)

बला किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अकाल और बाढ़ का सरकार ने मुकाबला नहीं किया, जैसा कि उनको करना चाहिए। सरकार ने जो अकालराहत कार्य चलाये, वह बहुत लेट चलाये, जबकि लोगों की मरने जैसी हालत हो गई, तब राहत अकाल कार्य चलाये। समय पर नहीं चलाए। लोगों की हालत बहुत ही क्षीण हो चुकी थी, उसके बाद भी पांच में से दो को काम दिया और फिर टास्क बेसिस पर वेजेज की जैसी घातक नीति रखो, जिसने लोगों का बहुत नुकसान किया। उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंहगाई के जमाने में दो आदमी कमाने के लिए जायं और मेहनत करके अपने बीबी बच्चों को खिलायें—यह उनके लिए सम्भव नहीं था। फिर भी किसी तरह से लोगों ने समय गुजारा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा समय शायद उनको आइन्दा देखने को नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष जी, इस अकाल का मुकाबला जो कुछ किया है वह जनता ने किया है। सरकार की तरफ से जो इस तरह का प्रबन्ध या वहां पर कि एक आदमी दिन भर काम करें, उसके बाद उसको पचास पैसे, पैंतालीस पैसे मजदूरी के मिलें। आपने यह तय कर दिया था कि हम सवा तीन रुपये देंगे, एक आदमी को, लेकिन सवा तीन रुपये कितने आदमियों को मिले हैं—इसका मुझे पता नहीं चला। इसलिए इन शब्दों को सुन कर कि राज्य सरकार ने अकाल और बाढ़ का मुकाबला किया है, मुझे दुःख हुआ। अकाल और बाढ़ का मुकाबला तो राजस्थान की जनता ने किया है।

उन्होंने यह भी फर्माया कि 13 लाख 11 हजार व्यक्तियों को रोजी दी गई है अकाल राहत कार्यों पर। मेरा निवेदन है कि यह 13 लाख 11 हजार किस तरह से हुए हैं। एक आदमी एक पखवाड़े में किसी काम पर लगा हुआ है, उस काम पर कुल पच्चीस आदमी हैं, उनमें से एक को निकाल दिया है दूसरे पखवाड़े में दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, काम करने वाले तो पच्चीस रह गये लेकिन संख्या 26 हो गई। तीसरे पखवाड़े में बी को हटा कर सी को लगा दिया। इस तरह आदमी तो पच्चीस के पच्चीस रह गये लेकिन संख्या 27 हो गई। इस तरह से जितने नाम आये हैं उनके हिसाब से 13 लाख 11 हजार हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने अकाल में मुतवातिर काम नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय ने जो हमारे यहां पर शीत लहर आयी है, उसके लिए खेद प्रकट किया है। माननीय राज्यपाल ने अभिभाषण में फर्माया है कि इसका जायजा लिया जा रहा है। यह किस तरह से लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्स गिरदावरी हो रही है, उसमें जायजा लेने की कोशिश है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बिना जनता के प्रतिनिधियों को पूछे जिन्स गिरदावरी की जा रही है। इसलिए इसमें वही होने वाला है जैसा कि अतिवृष्टि होने के कारण हमारे इलाके में अकाल पड़ गया, फिर भी जिन्स गिरदावरी में अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इस समय भी यही होने वाला है और हो रहा है। मैं अपने इलाके में हो

(श्री विजय सिंह)
कर आया हूं। मैंने इस तरह की परिस्थिति देखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में जिस जगह पर काम चालू थे, उस जगह काम इस तरह का दिया गया है कि वहां गेंती चलायेगा कोई तो वह गेंती रिबाउण्ड होकर ऊपर आयेगी। ऐसी जमीन पर काम दिया गया है और टास्क बेसिस पर पेमेन्ट किया गया है। इससे पेमेन्ट पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा अनपेड भी आज आठ नौ महीने से पड़ा है। राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि इस पखवाड़े का चुकारा आगे के पखवाड़े को छोड़ कर उससे आगे के पखवाड़े में कर दिया जायेगा लेकिन आज आठ नौ महीने के बाद भी चुकारा नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोरम नहीं है।

(गणपूरक सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महंगाई के बारे में निवेदन करूंगा, मंहगाई के ऊपर इस सदन के अन्दर तीन चार घण्टे की चर्चा हुई। उसके बाद में जो उत्तर दिया गया सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि आबादी बढ़ गई है तो महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है, कुछ चीजों का अभाव है, लोगों ने होर्ड कर लिया है, लोगों ने चीजों को दबा दिया है, इसलिए चीज बाजार में नहीं आ पाई है। इसलिए महंगाई को नहीं रोक सकते। यह अच्छा जवाब नहीं था। इसका हल निकालने वाली बात है मगर इसका कोई हल निकालने वाली बात मंत्री महोदय करते तो ज्यादा अच्छा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं वह इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन स्टेट मिनिस्टर मौजूद है। यदि आप अनाज की मंहगाई रोक पायेंगे तो जितनी मंहगाई दूसरी आवश्यक वस्तुओं पर है, वह रोकी जा सकती है और अनाज के लिए आपने क्या किया है। आपने सीधा 500 क्विंटल हर व्यापारी के पास रहने के लिए तो आदेश दे दिया लेकिन 500 क्विंटल वह कितने समय के अन्दर बाजार में लाकर उसको बेचना पड़ेगा, यह पाबंदी उस पर तो नहीं लगाई वरना तो जो मंहगाई है, वह दूर हो सकती है। आपने एक तरह से उसको होर्डिंग करने का चांस दिया है। भाई के नाम से, लड़के के नाम से 500 क्विंटल उन्होंने अलग अलग गोदामों में इकठ्ठा कर दिया लेकिन आपने यह नहीं तय किया कि 500 क्विंटल वह कब तक बाजार में बेच देगा। रीजनेबल समय चाहे एक माह दो माह आप तय करें लेकिन निश्चित मियाद के अन्दर वह बाजार में लाकर बेच दे तो सारी समस्यायें जो हैं, हल हो सकती हैं और अनाज के भाव एकदम गिर सकते हैं।

वितरण समितियां सारे जिलों में बनी हुई हैं लेकिन वे इन्इफेक्टिव हैं। आज वहां पर जिलाधीश, रसद अधिकारी, जिस तरह से चाहें काम करते हैं इसलिए इन वितरण कमेटियों का अध्यक्ष आप जिलाधीशों को न बनायें, सरकारी अधिकारियों को न बनायें और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का

(श्री विजयसिंह)

बनायें जो जनप्रतिनिधि हो चाहे पदेन हो, जैसे चाहे जिला प्रमुख हो, जब तक ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्ष नहीं बनायेंगे, तब तक वितरण समितियों से उद्धार होने वाला नहीं है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं गरीबी मिटाने वाली। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वह कहीं भी नजर नहीं आई। हम 144-145 कांग्रेस के सदस्य जीत कर आए हैं वह इसलिए जीत कर आए हैं कि हमने लोगों से वायदा किया है कि गरीबी मिटाने के लिए तैयार हैं। आज देखता हूं गरीबी मिटाने की बात इतनी मंद गति से चल रही है कि प्रगति की 'गति' तो नहीं रही केवल 'प्र' रह गया। सघन रोजगार की योजना जो हमने चलाई है, वह उस दिशा में एक कदम है लेकिन उसकी प्रोग्रेस क्या है। कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमने बैंक से लोन देने वाली बात की है, मगर लोन देना बंद कर दिया। जितने कदम उठाये, वे मंथर गति से चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता के सामने हम यह नारा अब नहीं दे पावेंगे कि हमने गरीबी मिटाई है। आप गरीबी मिटाने वाली बात को कहें और जो कदम उठा रहे हैं उनमें कोई गति न हो तो जहां के वहीं रह जाते हैं और उनकी तरफ हमारा कोई आगे का कदम नहीं बढ़ सकता। गरीबी मिटाने के लिए जो कार्य हाथ में लिए हैं, उनको तो गति देंगे ही, उसके अलावा भी आप सिंचाई साधन बढ़ायें, जितना रेनवाटर है उसको टैप करें, अंडरग्राऊंड वाटर को लिफ्ट देने का प्रयत्न करें, इसके छोटे छोटे बांध बनायें, जो बांध अकाल की योजना के हैं और किसी तरह से अधूरे छोड़ दिए हैं, जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है और आज उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उन अधूरे कामों को पूरा करायें और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की तरफ से हमारे यहां पर एक कलस्टर प्रोग्राम चल रहा है लेकिन उसके अन्दर गति नहीं है, वह भी इसी हिसाब से चल रहा है। गरीबी मिटाने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर बढाने के लिए, उत्पादन बढाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें। उसको भी गति देने वाली बात होनी चाहिए, वह जो कलस्टर प्रोग्राम है उसको और गति से चलाया जाए। सारे का सारा वजन खेती पर नहीं डाल सकते। इस तरह की बात होगी तो हो सकता है कि हम आगे जाकर निराश न हों। आज जितनी जमीन है, क्या आप समझते हैं कि सारी की सारी पर सिंचाई होती है और दोनों फसलें होती हैं।

एक माननीय सदस्य: कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री विजयसिंह: इस तरह के आपको दूसरे रास्ते भी ढूंढने होंगे और जब तक गांवों में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक केवल खेती पर आधारित होकर गांवों का उत्थान नहीं कर सकते। जितनी बरसात होती है उसी आधार पर पिलाई कर सकते हैं केवल आप जमीन एलाट करते चले जायं और लोगों को सूखी

(46)

(श्री विजयसिंह)

जमीन देते चले जायं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है।

मैं समझता हूं आपके जितने पानी के रैसोर्सेज हैं उसके आधार पर जमीन होनी चाहिये और उसका बंटवारा इकानामिक होल्डिंग्स के रूप में करें और शेष ग्रामीण आबादी को छोटे छोटे उद्योगों में लगायें। जितना गांवों में खेती पर खर्चा कर रहे हैं उतना ही खर्चा गांवों के औद्योगीकरण में लगाना चाहिये जिससे गांवों की हालत सुधरे। आज आप काश्तकारों को कोई सुविधा नहीं दे पाते, सीमेंट नहीं दे पाते, खाद नहीं दे पाते, तेल नहीं दे पाते, घासलेट नहीं दे पाते, जो उनको आवश्यक वस्तुएं हैं, वह उनको नहीं दे पाते। इस साल अच्छी बरसात होने के कारण और सिंचाई के अच्छे साधनों की भी काफी गुंजाइश थी लेकिन बीज न होने के कारण वह बुवाई नहीं कर सके और वसूली का जब सवाल आया तो अतिवृष्टि को अच्छी बरसात कह कर कि अकाल मिट गया है, सब सालों की यानि 7 सालों की वसूली एक साथ किसानों से करली और दूसरी ओर गरीबी मिटाने की बात करते हैं, यह अनुचित है। काश्तकार को सभी साधन दें, जितने भी तरक्की करने के लिएं साधन हैं उनको दें उसके बाद अतिवृष्टि या अनावृष्टि से पीड़ित आदमी हो, उससे 7 साल की वसूली एक साथ भी करें तो थोड़ी समझदारी मानी जा सकती है।

भीलवाड़ा जिले में सैटिलमेंट हुआ उसमें तीन तीन गुना लगान [illegible] [illegible]

कर्मचारी सैटलमेंट विभाग के हैं इनकी कई त्रुटियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग बहुत ही करप्ट हैं वे अपने मन चाहे ढंग से लगान लगाते है। इन्होंने किसानों के लिये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करदी है। आज इनकी बदौलत यह हालत है कि गांव का किसान परेशान हो रहा है। इससे तो अच्छा हो कि इस सैटलमेण्ट डिपार्टमेन्ट को ही समाप्त कर दें। किसान को सबसे बड़ी बात तो यही चाहिये कि उसको अपनी जमीन का टाइटल मिल जावे। उसे यह मालूम हो जावे कि उस जमीन को उपभोग करने का उसे हक है इसके लिये राज्य सरकार को इस विभाग की क्या आवश्यकता है। वैसे ही राज्य सरकार अपने राजस्व अधिकारियों द्वारा जैसे पटवारी वगैरह हैं उनसे ही करवाते रहना चाहिये। यदि जमीन की किस्म में तब्दीली आती है यदि बारानी भूमि पीवल हो जाती है उस पर पीवल का लगान राजस्व अधिकारी पटवारी की रिपोर्ट पर लगादे। यदि बन्जड़ भूमि आबाद हो जाती है तो रेकार्ड पर वैसा दर्ज करले। जो काम सरकार 20 साल 25 साल बाद कराती है वह रोजमर्रा होता रहे तो क्या ऐतराज है। वरना सैटलमेन्ट विभाग तो भ्रष्टाचार को ही बढ़ा रहा है वह किसान पर दुगना तिगुना लगान लगा रहा है। होता यह है कि जब गांव में सैटलमेन्ट विभाग के अमीन आते हैं तो गांव वालों को अमीन साहब के लिये दूध, दही, रहने और खाने का प्रबन्ध तक करना पड़ता है। [illegible]

[illegible]

(श्री विजयसिंह)

पढे लिखे होने की वजह से उनको रिश्वतें देते हैं। वे लोग बिना रिश्वत किसी का भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिये यह राज्य सरकार के हित में भी है कि वह सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट को ही उठादे और नेचूरल वे में राजस्व अधिकारियों द्वारा ही यह रुटीन में काम होते रहें। यह चेन्ज होना बहुत जरूरी है। ताकि भूमि संबंधी जो भी तबदीली हो वह भी रोजमर्रा होती रहे और काश्तकार को कष्ट नहीं उठाना पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बात मैं और कहूँगा। फिर मैं समाप्त कर दूंगा। अभी हमने ऐसा अखबारों में पढ़ा कि पंचायतों के चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। फिलहाल शायद उनको 8-10 महीने के लिये सरकार आगे सरका रही है। राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है यह तो राज्य सरकार की मरजी पर है मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि कई साल से चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतें एक प्रकार से मृतप्राय सी हो गयी हैं उसके पास करने को कोई काम नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि न्याय पंचायतों का काम इन्हीं ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाय ताकि वापिस उनमें जान आ सके। नहीं तो इन आठ दस महीनों में कुछ भी काम नहीं होने वाला है और न्याय पंचायतें जो कि अब तक एक तरह से बेकार हैं उन्हें खतम कर पंचायतों को उनके पावर्स दे दिये जायं। राज्य सरकार यह कार्य वैसे ही पंचायतों के चुनाव के बाद करने को जा रही है। वह अभी ये करदे तो फिर आप अगर पंचायतों के चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं मेरे सुझाव के अनुसार कार्य करने से जो पंचायतें एक तरह से निष्क्रिय हो गयी हैं उनमें जान आ जायेगी।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। वह है फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के बारे में। आज हमारे राज्य में जो अनाज की वितरण व्यवस्था इस एफ.सी.आई. के द्वारा की गई है उससे हमारे व्यापारियों और जनता को बहुत बड़ी भारी दिक्कत रहती है क्योंकि जब व्यापारी को डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर परमिट अनाज के लिये काट कर देता है तो उन व्यापारियों को कई दिन तक माल नहीं मिलता है और काफी ज्यादा समय उन्हें माल लेने के लिए नष्ट करना पड़ता है। अभी ऐसी चर्चा चली थी कि राज्य सरकार इस एफ. सी. आई. का प्रशासनिक नियन्त्रण अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कन्ट्रोल अपने हाथ में आ जायेगा तब कुछ परेशानी व्यापारियों की कम होगी। इसके लिये मेरा सुझाव राज्य सरकार को यह है कि जब तक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल अपने हाथ में नहीं आवे तब तक ऐसा किया जाये कि राज्य सरकार एफ. सी. आई. से जो भी अनाज पूरे राज्य के लिये लेना चाहे वह ले और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट्स में अपने गोदाम कायम कर जितना जिस जिले को देना हो भेज दे ताकि बाद में जरूरत पड़े तो डी. एस. ओ. व्यापारियों को परमिट दे तो वह व्यापारी लोग उन गोदामों से अनाज उठालें। इससे दिक्कत नहीं होगी। वैसे देश के लिये एक फूड कारपोरेशन होना अच्छा है क्योंकि यदि मद्रास

(श्री विजयसिंह)

गवर्नमेंट को अनाज की जरूरत हो और पंजाब में ज्यादा अनाज हो तो वह एफ.सी. आई. के पास से ही ले। एक केन्द्रीय भण्डार इन्टर स्टेट अरेन्जमेंट के लिये जरूरी है।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज तक हमारे प्रान्त में से सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं हुई है। यह सबसे खराब बात है और हमारे समाज के लिये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंसान का मैला दूसरा इंसान अपने सिर पर ढोये। इसके लिये हम अगर केन्द्रीय सरकार की तरफ देखें कि वह जब पैसा देगी समाज कल्याण विभाग को तब इस प्रथा का अन्त होगा, यह गलत बात है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने आज तक इतने पैसे नहीं दिये हैं कि यह प्रथा हटाई जा सके। इसके लिये तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। चाहे इसके लिये अपने को अभी दूसरी योजना से पैसे की कटौती करके इसमें लगाना पड़े, और इस प्रथा को समाप्त करना पड़े। हमारे यहां पर केकड़ी ब्यावर और आबूरोड़ वगैरह में यह प्रथा समाप्त करदी गई है लेकिन इतने बड़े राजस्थान में और भी बहुत सी जगहें हैं अत: इसको हमें समाप्त करनी चाहिये। इसके लिये मेरा सरकार से सुझाव है, कि वह स्टेट के अपने बजट में ऐसा प्रावधान करे जिससे यह प्रथा पांच साल में तो समाप्त हो ही जाय।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा अभी लोढ़ाजी इस सदन में नहीं हैं कल वह आसीन्द के चुनावों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो वह कह रहे थे वे सभी बातें बेबुनियाद थीं। वे जिन गांवों का नाम बता रहे थे वे सारे गांव मेरे ही चुनाव क्षेत्र में थे। जिन सरकारी अधिकारियों का नाम बता रहे थे वे सब गलत थे क्योंकि अनफोरचूनैटली वहां मैं भी मौजूद था...

श्री परसराम मदेरणा : अनफोरचूनेटली नहीं फोरचूनेटली।

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलाल जी व्यास जैसे ईमानदार व्यक्ति हैं जिनकी राजस्थान में ईमानदारी की साख है ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी बात करना कितना शर्मनाक है वह हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट लौह पुरुष हैं। उनके लिए यह कहना कि सेठों से मिलीभगत करके या भ्रष्टाचार से इन्होंने इलेक्शन जीता सरासर गलत है। अब चूंकि जनसंघ वालों ने आसीन्द के इलेक्शन में मार खायी इसलिए यहां पर सदन में खिसियानी बिल्ली की तरह खम्भा नोंच रहे हैं और कांग्रेस को सदन में गालियां निकाल रहे हैं। वह जो आरोप लगा रहे थे मैं उन्हें मानने को तैयार नहीं और न ही इस सदन का कोई समझदार सदस्य ही मानने वाला है बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किशनपोल बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा था उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किशनपोल बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री भीमसेन)

सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था इस सदन में उस पर इस पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो बिल्कुल सही है कि राजस्थान प्रान्त एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है और राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी भारी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का तात्कालिक हल निकलना चाहिये और अगर हम इस समस्या का कोई तात्कालिक हल नहीं निकालते हैं तो इससे हमारा जन जीवन ग्रसित हो जायेगा। इसके लिये हमें हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना चाहिये। राज्य सरकार जनता की इस स्थिति से वाकिफ है लेकिन इसके लिये राज्य सरकार के सिर्फ सजग रहने से ही काम नहीं चलेगा अपितु हमें अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमको चाहिये इस पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये हमें अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाना होगा और पूंजी का नियोजन अनाज का उत्पादन और दूसरे प्रोडक्शन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना होगा। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें छोटे सिंचाई के साधनों को बढ़ाना होगा ताकि तत्काल रिटर्न मिले इससे मंहगाई में कमी आयेगी। इसके लिये हमें कृषि के क्षेत्र में विकास करना होगा। आज स्थिति उपाध्यक्ष महोदय यह है कि हमारे यहां कृषि की यह स्थिति है कि कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय में आपस में होड़ सी लगी हुई है। आज हम कृषि का विकास करना चाहते हैं तो कृषि विभाग तो कहता है कि कृषि अनुसन्धान का कार्य हमारे डिपार्टमेन्ट के नीचे आना चाहिये और कृषि विश्वविद्यालय कहता है कि कृषि अनुसन्धान का कार्य हमारे हाथों में होना चाहिये जिससे कि राजस्थान में कृषि के सम्बन्ध में सब क्षेत्रों में अनुसन्धान हो सके। आज बीकानेर और राजस्थान के उस पश्चिमी क्षेत्र के लिये आज तक इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार का कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया है जो कि बहुत ही आवश्यक है। राजस्थान कैनाल आज विश्व में सबसे बड़ी कैनाल है एवं लिफ्ट कैनाल है उसके बनने से पहले से है उसके लिए क्या पैटर्न क्या हो, उसके लिये काश्तकारों को प्रशिक्षित किया जाय, कृषि के लिये सब प्रकार के अनुसंधान किये जायं यह सब निहायत जरूरी है और मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में समय रहते हुए लूणकरणसर के आस पास कृषि अनुसंधान व प्रदर्शन फार्म स्थापित करेगी।

उस क्षेत्र में पशुपालन के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा। अभिभाषण में कहा गया है कि डेयरी की स्थापना के लिये राजस्थान में सक्रिय कदम उठायेंगे लेकिन यदि दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिये पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम नहीं अपनायेंगे तो मुझे भय है कि जिस लक्ष्य को लेकर सरकार चलना चाहती है वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यदि दूध उपलब्ध नहीं होगा तो प्लान्ट सूखे पड़े रहेंगे, और राजस्थान की जनता जो यह आशा लगाये बैठी है कि उसको अच्छा दूध मिलेगा उसकी वे आशायें पूरी नहीं होंगी। इन क्षेत्रों का निश्चित रूप से सर्वे करना चाहिये कि आया वहां पर दुग्ध

(श्री भीमसेन)

दूध उपलब्ध होगा या नहीं और यदि दूध उतना उपलब्ध नहीं होता है तो इस ओर आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिये। वरना इस ओर पूंजी का नियोजन बेकार जावेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और पशुपालन विभाग को सक्रियता बरतनी चाहिये यह बड़ा आवश्यक है।

माननीय सदस्यों ने राजस्थान की सबसे बड़ी मुख्य समस्या को अकाल की समस्या बताया है। विशाल मरुप्रदेश की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे प्रदेश के सामने है वह मरु क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में है। एक प्रश्न के उत्तर में योजना मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि राज्य सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है कि अलग से डेजर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी कायम की जाय। वे चाहते हैं कि अलग अलग जिलों के जिलाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना कर कार्य किया जाय मैं समझता हूं कि यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि यह कार्य जिलाधीश नहीं कर पायेंगे। यह तो केवल प्रश्न को टालने वाली बात है। राजस्थान में जिलाधीशों को इतना काम दे रखा है कि जिस किसी काम को टालना होता है उसको उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। इसलिये मरु विकास जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अलग से मरु विकास अधिकरण बनाना आवश्यक है वरना मरुस्थल को जो एक विशाल समस्या है उसका हल नहीं कर पायेंगे।

राजस्थान में जब जब और जहां जहां पर अकाल पड़ते हैं तो उस समय विकास के कार्य, राहत के कार्य खोलते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को यह तो भलीभांति मालूम है कि किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां पर अकाल पड़ते हैं तो क्यों नहीं सरकार पहले से ही उन जिलों के लिये कोई स्थायी योजनाओं का कार्य शुरू करती है अथवा योजनायें बना कर अपने पास रख लें, जैसे कहां पर माइनर इरीगेशन का कार्य करना है, कहां पर सड़कों के कार्य शुरू करने हैं और कहां पर क्या विकास के कार्य करने हैं, उन अकाल से पीड़ित क्षेत्रों के लिये अकाल राहत योजना पहले से ही तैयार करके रखें ताकि अकाल पड़ने पर तुरन्त अकाल राहत कार्य शुरू किये जा सकें।

इसी प्रकार फोडर बैंक्स के लिये भी निवेदन करना चाहता हूं। अकाल के समय में फोडर बैंक की स्थापना करते हैं और उस समय ही इस की व्यवस्था करते हैं कि कहां से फोडर मंगाना है। अकाल के समय से पहले ही फोडर बैंक की व्यवस्था कर ली जाय तो क्या हर्ज है? इसमें अकाल के समय में इस प्रकार की व्यवस्था करने से जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है और समय पर पूरा फोडर भी नहीं मिल पाता है और खर्चा भी अधिक करना पड़ता है उन सब से बचा जा सकता है। इसलिये इस प्रकार की फोडर बैंक्स योजनाओं को पहले से ही कार्यान्वित कर लिया जाना चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है।

बीकानेर जिले को औद्योगिक घोषित करने पर उद्योग पनप सकें। राजस्थान में,

(श्री भीमसेन)

उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली आदि क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित हैं लेकिन इस हिस्से को उद्योगों के मामले में बहुत ही पिछड़े हुए घोषित किये जा चुके हैं जब भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि बीकानेर में छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज हैं। लेकिन इस डिवीजन को पिछड़ा घोषित न करना इसको और अधिक पिछड़ा रखना है। राज्य सरकार यह जवाब देती है कि औद्योगिक दृष्टि मे पिछड़ा घोषित करना भारत सरकार का काम है। जो आंकड़े है और जिस दृष्टि मे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए वह सब सामने है। यह भी कहा जाता है कि बिजली की वहां प्रति व्यक्ति औसत खपत ज्यादा है। उसका उत्तर यह है कि वह इसलिये ज्यादा है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये ज्यादा बिजली खर्च होती है पर कैपिटा। लेकिन सरकार यह कहती है कि बिजली की खपत ज्यादा है इसलिये उद्योग धन्धे ज्यादा हैं। ये सामने आंकड़े हैं उनके आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। वहां पर राजस्थान नहर आरही है। यह स्वाभाविक है कि कृषि पर आधारित उद्योग-धन्धे वहां पर बढ़ेंगे। पिछड़ा घोषित करने से उद्योग धन्धों को रिबेट मिलती है। इनकम टैक्स में और दूसरी सहूलियतें उनको मिलती हैं और यदि इसको पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे, उद्योगों के मामले तो ये रियायतें और सहूलियतें उनको नहीं मिल पायेंगे और इस दृष्टि से लोग जो उद्योग धन्धे लगाना चाहेंगे वे वहां पर नहीं लगायेंगे। इसलिये इस दृष्टि से भी इसको औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना चाहिये।

बीकानेर में सबसे अधिक ऊन उत्पन्न होती है और उस पर आधारित उद्योग-धन्धे बढ़ाये जा सकते हैं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित नहीं करने से वहां पर ऊन के उद्योग धन्धे चालू करने से भी पीछे हट रहे हैं।

बीकानेर के आस पास बुनकर हाथ से काम करने वाले लोग सूत के अभाव में बेकार हैं यदि उनको अधिक तादाद में सूत उपलब्ध हो जाय तो उन लोगों को काम मिल सकता है। बीकानेर के पास अच्छे अच्छे बुनकर हैं और इस काम में रुचि रखने वाले लोग है। यदि हमारी सरकार लघुउद्योग विभाग की ओर से वहां पर Woolen Production Centre खोल दे और बिक्री की व्यवस्था कर सकें तो क्रानिकल Draught अफेक्टेड एरियाज हैं उनको काम दे सकेंगे।

होस्पिटल्स के लिये मेडिकल विभाग के द्वारा कम्बल आदि खरीदे जाते हैं। पुलिस एवं अन्य सहकारी विभाग ऊनी माल खरीदते है पर यदि यह सब ऊन का माल खरीदने के लिये वहां लघु उद्योग निगम उत्पादन केन्द्र स्थापित कर दे तो ऊन का माल उनको सस्ती दर पर मिल सकेगा। कम्पीटिटिव रेट्स पर खरीद सकेंगे तो आवश्यकता की पूर्ति भी होगी और वहां के लोगों को नये रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आवश्यकता है कि प्रदेश में बचत के साधन अपनाये जांय।

(श्री भीमसेन)
भोजन के समारोह आदि होते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा कर खर्च में हर प्रकार से बचत के साधन अपनाने चाहिये जिससे कि प्रदेश का अधिक विकास हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री **रमेशचन्द्र सैनिक** (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उन पर धन्यवाद का प्रस्ताव किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उस पर मैं अपने विचार रखने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन के साथ साथ अपने जिले के जो अभाव-अभियोग हैं उनको ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हम यहां बैठकर यह विचार करते हैं कि पहले हमने क्या किया है, आज क्या करने जा रहे हैं और कल क्या करेंगे। इन तीन चीजों को हम यहां बैठकर देखते हैं और तै करते है। इन कामों के लिये वित्तीय स्थिति देखनी पड़ती है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और उसी के अनुरूप हमारी तैयारी होती है।

अब हमें देखना यह है कि हमारी वित्तीय स्थिति को दृढ़ बनाने में बाधक तत्व क्या हैं। इसमें एक तत्व तो वह जो नेचर की तरफ से हैं। दूसरा है इन्सान के द्वारा पैदा किया हुआ।

प्रकृति का प्रकोप जब हमारे सामने आता है तो हम एक आवाज से, एक हिम्मत से उसका प्रतिरोध करते हैं। उसका प्रतिरोध करना हमारी सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी हो जाती है। हम सबका कर्तव्य हो जाता है। इसमें भी वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल ये प्रकृति के ऐसे प्रकोप हैं जो सबसे अधिक नुकसान हमारा करते हैं। इसके समाधान के लिये सरकार ने समय समय पर काफी प्रयास किये हैं । गये वर्षों में जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने भी बताया है हमने 60 करोड़ का खर्चा किया है, 13 या 14 लाख के आस पास लोगों को काम दिया है उनकी सहायता की है।

राजस्थान की जनसंख्या 2।।। करोड़ के आस पास है और इसमें भी 80।85 प्रतिशत जनता ग्रामीण है, किसान है, मजदूर है । इस संख्या को देखते हुए जितनी संख्या में राहत पहुंचाई गई है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोगों को जितनी राहत अकाल आदि प्रतिकूल कठिनाइयों में मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल सकी, न मिल रही है, न मिलने की अभी सम्भावना है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिये कि इन सबको राहत मिल सके और अकाल और दुर्भिक्ष हमारे यहां से मिट सकें।

अभी अभी फरवरी में ही एक शीत लहर का प्रकोप हमारे यहां हुआ। किसान बहुत निराश हुआ। उसकी पिछली दो-तीन फसलें लगातार खराब होती आई हैं। किसान को इस फसल पर थोड़ी आशा थी। पर वह आशा भी निराशा हो गई । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । शीत लहर की लपेट में वे फसलें आई हैं

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

पहले बोई गई थीं। दिवाली से कुछ बाद में बोई गई फसलें भी चपेट में आई हैं या वे फसलें आई हैं जो कुओं से सिंचित होती हैं। कुओं द्वारा सिंचित फसलें पहले बोई जाती हैं क्योंकि गरमी शुरू होते होते कुओं के पानी के भी कम होने की आशंका रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का पूरा हिस्सा 1।4 चम्बल कमाण्ड एरिया में आता है। उसमें 3।4 भाग ऐसा है जो कुओं से या तालाबों से सिंचित है। इस तरह से इसे चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला चम्बल कमाण्ड का, दूसरा बरड, तीसरा खेराड और चौथा नागर चाल है। बूंदी की तहसील हिण्डोली की तहसील नेनवा की तहसील इसमें आती हैं। यहां नुकसान पहुंचा है। जो पहले भी अकाल की चपेट में था। इन में बहुत निराशा है। अगली फसल की बात तो आगे आवेगी आज तो अपने पेट भरने इनके लिये समस्या बन गई हैं। तो आज इन किसानों को निराशा में पड़ने से बचाया जाय।

इसके अतिरिक्त दूसरी परेशानियां, कठिनाइयां हम लोगों में से ही जनता द्वारा पैदा की हुई होती हैं। विशेष तौर पर आज जो विरोधी पक्ष के लोग इतना करते हुए भी यह कहते नहीं चूकते कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे स्थान पर वे होते तो उनकी भी यही दशा होती। काम करने वाला हमेशा बदनाम होता है। उदाहरण के तौर पर परिवार के मुखिया को आप ले सकते हैं। उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं कहता हूं कि परिवार के मुखिया की हैसियत से पिछले 25।26 सालों में कांग्रेस सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है। अब जो लोग सत्ता के लिये विरोध करते हैं वे करते रहेंगे, उसकी हमें परवाह भी नहीं करनी चाहिये। मैं उनकी बातों का उत्तर दिये बिना नहीं रहूंगा। आज बार बार यह कहा जाता है कि बंगला देश की लड़ाई लड़ने से सब चीजें महंगी हो गई और उनका अभाव हो गया। मैं स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ है, वह परेशानियों का ही मुकाबला करता रहा है हमारी बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है व साम्राज्यवादियों की चाल में फंसकर हमें लगातार परेशान करता रहा है। परिणाम यह हुआ कि हमारी अधिकांश शक्ति उधर लगी। जो हमारी गरीबी की स्थिति को दूर करने में लगनी चाहिये थी। 71 मे जाकर हमने पाकिस्तान को वह सबक सिखाया है कि उसके अस्तित्व को ही अब खतरा पैदा हो गया है। उसका एक हिस्सा उससे अलग हो गया है। रहे सहे में आपस में ही लड़ाइयां चल रही हैं। यह हमारी बहुत बड़ी सैनिक उपलब्धि है। हमारी सैनिक परम्परा शानदार रही है। उसी परम्परा को हमने इस बार चार चांद लगा दिये हैं। दुनिया के एक बड़े सैनिक विशेषज्ञ ने जैसा कि बहुत पहले कहा था कि हिन्दुस्तान की फौज, इंग्लेण्ड का मस्तिष्क और कनाडा का धन अगर ये एक जगह मिल जावें तो सारे विश्व पर छा सकते हैं। हमारे भारतवर्ष का हरएक नागरिक अच्छा आदमी है इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है।

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय मैंने तो शुरू भी नहीं किया है। मैं अपने विषय पर आ ही जाता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ठहरिये।

(गणपूरक के पश्चात्)

(गणपूर्ति सूचक घण्टी)

श्री रामकिशन : श्रीमान खेतसिंह जी आप तो क्लोजर मूव कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यों का काम ही कोरम रखना है। वे कोरम पूरा रखें, यह भी वे नहीं रखते हैं।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय हम आज़ाद हुए एक तरफ पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बन कर हमसे अलग हो गये। बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दुस्तान का कटकर अलग हो गया और बहुत बड़ी परेशानियां आई, जिनका मुकाबला किया। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं ज्यों ही देश आजाद हुआ कि कई प्रकार की समस्यायें आ गई। सबसे पहले हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद हो गया। उसको नियन्त्रण करना हमारी भारत सरकार का काम हो गया था। इसके बाद 47-43 में भारतवर्ष ने यू.एन.ओ. में जाकर काश्मीर का प्रश्न उठा था। इसके बाद चाइना और पूर्वी-पश्चिमी पाकिस्तान तीनों ने मिलकर हमारी सीमाओं को घेर लिया और मेकमोहन रेखा को मिटाना चाहते थे, जो चाईना की सीमा थी वह उसके साथ लगी थी। इसलिए उससे लड़ना पड़ा। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का संकट आ गया। यह चाइना से मिलकर भारत में घुसपैठ करना चाहता था, उसको हटाया। चाइना पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है. उसके लिए भी हमारा संघर्ष है। पिछले दिनों डाकुओं का प्रश्न आ गया उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ हल किया, सन् 50 में हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ना पड़ा, गोवा को भी मुक्त कराया। 62 में चाइना ने आक्रमण कर दिया उसका मुकाबला किया। इसी प्रकार 65 में पाकिस्तान का मुंह तोड़ा। माननीय सदस्य कह देते हैं कांग्रेस जहां कहीं कोई बात हो बंगला देश कह कर टाल देती है। यह बात नहीं है। आजादी के प्रारम्भ से हमने परेशानियों का मुकाबला किया है। अनेक प्रकार की समस्यायें आती रही हैं और उनको हिम्मत और धीरज के साथ निपटाया गया है।

इन सब समस्याओं के साथ हमारी प्रगति का प्रश्न भी है। हमने इन सभी समस्याओं को देखा और निराकरण किया। पाकिस्तान ने सारे के सारे युद्ध सम्बन्धी उपकरण बाहर से प्राप्त किये लेकिन हमने युद्ध सम्बन्धी सामग्री बाहर से नहीं ली। बल्कि 62 की लड़ाई के बाद हमारी युद्ध सामग्री इतनी मजबूत हो गई कि हमने पाकिस्तान के पैटन टैंक, शर्मन टैंक और जैट विमान को भी धराशायी कर दिया। सारी दुनिया में यह आश्चर्य का विषय था कि हिन्दुस्तानियों ने पैटन टैंक और जेट विमानों को कैसे तोड़ दिया, इतनी शक्ति कहां से आ गई? हिन्दुस्तान का नाम सारे यूरोप में छा गया कि हिन्दुस्तान ने थोड़े समय में प्रगति की है लेकिन इसका अभि-

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)
प्राय यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जायं..

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब 10.5 मिनिट और लूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। संकट में जो हमारे साथियों को मदद करता है वही तो वास्तविक साथी होता है। जो आज खाद्य पदार्थ हैं तेल, क्रूड आइल, लूब्रीकेटिंग आइल, खाद, बीज ये सब केवल राज्य सरकार की ही बात नहीं है। ये सब जरूरत की चीजें हैं इसलिए दूसरों को भी इन पर विचार करना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब कल सरकार देगी।

श्री शिवचरण माथुर : सरकार के ही अंग हैं, सरकार के पार्ट एण्ड पार्सल हैं।

श्री रमेशचन्द्र : हमें अब देखना यह है कि पुलिस इस काम में कितनी मदद करती है, कितना सहयोग देती है, सरकारीकरण करके किसी चीज को सौंप देती हैं तो वे अपने मनमाने ढंग से इसका उपयोग करते हैं। इसलिए यह समझाया जाय कि राष्ट्रीयकरण किया है तो इसमें उनका भी हाथ है।

इसी प्रकार लेवी का प्रश्न है..... दूसरी दूसरी जो सारी चीजें हैं, जो चरण सरकार के मंहगाई को कम करने के हैं, व्यवस्था को सुधारने के हैं और शान्ति लाने के हैं उसमें मैं यह सोचता हूं कि जो कानून हम यहां बनाते हैं उनमें कोई ताकत नहीं हैं, उन कानूनों में कोई दम नहीं है। अगर हम कानून की मदद से आदर्श उपस्थित करें तो लोग अपने आप कानून की सारी परिभाषाओं को समझ जायेंगे। अगर भ्रष्ट आचरण करने वालों को गधों पर बिठाया जाय, उनका काला मुंह किया जाय और सारे शहर में घुमाया जाय तो उसका असर जनता पर पड़ता है लेकिन आज कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गये, कितने करप्ट आदमी पकड़े गये। यदि कानून में शक्ति आ जायगी तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था ठीक हो जायगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कहा हमने बहुत बड़ी भारी प्रगति की है, यह सब भौगोलिक स्थितियों पर आधारित है चाहे व्यास नदी का सवाल हो, रावी का सवाल हो, माही का सवाल हो, पाली जेतारण और किसी का सवाल हो सब पर भौगोलिक अवस्थायें लागू होती हैं। जहां छोटे छोटे बान्ध बनाये जा सकते है, बनवाये जाने चाहिये। मैंने सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में छोटे छोटे बान्ध बना दिये जायं, इसमें काफी सिंचाई का काम हो सकता है लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। मेरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाय और उस तरफ ध्यान दिया जाय।

26-3-73 को राज्य सरकार ने मुझे यह बताया था कि 8325 एकड़ भूमि जो कमान्ड एरिआ में नहीं है लेकिन उसको कमान्ड एरिया में ले रखी है। ये आंकड़े है जो कमान्ड नहीं हैं उसको कमान्ड

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

में घोषित कर रखी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था 57 से चली आ रही है उसके रेगुलराइजेशन आप हल कर दें। इसी प्रकार सिंचाई के लिये जहां पानी का अभाव है।

(अश्रव्य)

नेनवा तहसील में पाताल तोड़ कुओं का निर्माण किया जाना चाहिये। अगर यह बात सही है तो बैंक से ऋण लेकर किसानों को सुविधा दी जाय जिससे किसानों की भुखमरी खतम हो जाय। हमारा क्षेत्र सहकारिता का क्षेत्र है और सहकारिता के आधार पर काफी काम किया जा सकता है और यही केवल वहां आकर्षण का केन्द्र है। सहकारिता ही एक ऐसी संस्था है जो किसानों को कुछ दे सकती है। इसमें सरकार को और किसानों को पार्टीसिपेट करना चाहिये, उसमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। 80 परसेन्ट देहाती है और 20 पर्सेन्ट शहरी है। मेरा निवेदन है कि 100 में से केवल 10 के 10 शहरी हैं।

अब मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में एक कोआपरेटिव सेक्टर में फैक्टरी है और यह 1962-63 में बनी थी। जितनी रकम से यह बनी है उतनी रकम से दीवालिये में चल रही है। उस समय यह फैक्टरी 2॥ करोड़ रुपये में बनी थी और यदि आज उसको बनायें तो वह 10 करोड़ से कम नहीं बैठेगी तो उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। गत वर्ष ही यह अच्छे ढंग से चली थी क्योंकि उस समय जो चम्बल डवलपमेन्ट कमिश्नर थे उन्होंने इसके लिए काफी कुछ किया। वह किसानों के साथ बैठते थे। उन्होंने वहां पर आफिस वर्क छोड़ दिया और किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को हल करते थे और परिश्रम करते थे। लेकिन अभी जो चम्बल डवलपमेन्ट कमिश्नर हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहां पर उपाध्यक्ष महोदय, चार पंचायत समितियां हैं। तालेड़ा में 1972–73 में 120 एकड़ में शुगरकेन था और इस साल 1500 एकड़ में है। केवल इन्सेन्टिव देने से यह केशोरायपाटन की फैक्टरी काफी अच्छा लाभ दे सकती है। केशोरायपाटन में गत वर्ष में 30 हजार एकड़ में और 1973–74 में 5500 एकड़ में रही। अब पंचायत नेनवा बचती है। इस वर्ष 5 हजार एकड़ में है और हिंडोली में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और जहां सिंचाई के साधन भी ज्यादा नहीं हैं। वहां पर एक तो मीडियम स्कीम है और दूसरी एक दो माइनर हैं। उनके पास जमीन थोड़ी होते हुए भी गत वर्ष 6500 एकड़ में गन्ने की खेती रही और इस वर्ष 8700 एकड़ में रही। अब यहां खेद का विषय यह है कि जो हमारी फैक्टरी चल रही है उसका साल में क्रशिंग पीरियड 150 दिन होता है और रोजाना का [illegible] पर 1250 टन का कन्जम्पशन है और यदि हम इतने दिनों तक इसको चलायें तो 1 लाख 87 हजार 500 टन गन्ना देना पड़ता है और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर एकड़ 25 टन भी लें तो इस फैक्टरी को चलाने के लिए 8000 एकड़ में गन्ना पैदा करने की आवश्यकता है। इसके बाद छोटी मोटी छः सात खाण्डसारी की यूनिट्स हैं और उनका कन्जम्पशन भी थोड़ा है। उसमें 400 एकड़ है। इस प्रकार 9000 एकड़ गन्ना खर्च हो तो बाकी 10200

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

एकड़ बचा उसका क्या होगा। वहां पर सहकारिता के आधार पर दो मिलें और लगने वाली हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी स्कीम हो तो किसानों को रोटी देने के लिए और परेशानियों से बचाने के लिए उन किसानों को जो कि सरकार पर ही आधारित हैं उनको जिन्दा रखने के लिये निश्चित रूप से एक दो मिलें वहां पर लगाई जानी चाहिए।

इसके बाद में बिजली के बारे में कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के लिए दो चीजें ही सबसे ज्यादा महत्व की हैं एक तो बिजली और दूसरे पानी। बिजली और जल दोनों ही बहुत विशेषता रखते हैं। अभी हमने कुछ अच्छे काम शुरू किये हैं लेकिन उनके पूरा होने में काफी देरी लगती है। अगले वर्ष 600–700 गांवों को बिजली देने जा रहे हैं। आप बिजली दीजिए मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन जहां प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए।

इसके बाद डेरी के बारे में निवेदन करूंगा। जहां जहां पर आबादी है वहां पर तो आप निश्चित रूप से डेरी का प्रसार कर रहे हैं और वहां सब जगह डेरी होनी चाहिए। यह हमारे जीवन का एक अटूट अंग है लोगों के जिंदा रहने के लिए। इसलिए जहां भी आप डेरी खोल रहे हैं वह तो कुछ स्वागत योग्य कार्य है लेकिन अब जो जिले रह गये हैं उनके अन्दर भी यह होना जरूरी है। इससे चहुँ ओर विकास होगा।

उद्योग धन्धों के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई है। उपाध्यक्ष महोदय हमारे जिले का 1924 में स्टेट के जमाने में सर्वे हुआ था और वह सर्वे इस बात का हुआ था कि हमारे पास खनिज सम्पदा कितनी है। उसको देखने से पता लगेगा कि बूंदी जिला खनिज सम्पदा में सबसे आगे है और सबसे ज्यादा मालदार है लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं है। अभी गत वर्षों में भी वहां पर सर्वे हुआ है। उसको यों समझिये कि यदि 100 फैक्ट्री भी लगाई जायें तो 200 वर्षों तक वह खनिज सम्पदा चल सकती है। पाली, सिरोही, कोटा और सीकर को सुना है कि इन्डेन्ट आने वाले हैं तो क्या कारण है कि बूंदी का नाम उसमें नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर अपार खनिज सम्पदा है उसकी भी कद्र की जानी चाहिए। वहां पर लोहा है, तांबा है, शीशा है और मारबल है। जहां कोई खान विकास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय; वहां सुमेर गांव है जहां मारबल काफी मात्रा में है और यदि उस गांव को बिजली दे दी जाती है तो वह गांव और क्षेत्र ऐसा है कि जिसका स्वतः ही विकास हो जायेगा। मेरे दो साल के कार्यकाल में एक भी गांव को बिलजी नहीं दी गयी। क्या पता मैं कमजोर हूं या पता नहीं कोई मेरी सुनता नहीं है। हमारे बूंदी में सिलीका सम्पदा है जिसको कन्हैयालाल घाटी वाले अब तक लेते जा रहे हैं। जब इसकी लीज़ दी गई थी तो यह शर्त थी कि वह वहां पर ग्लास फैक्ट्री लगायेगा लेकिन पता नहीं क्यों यह ग्लास फैक्ट्री तो लगी नहीं लेकिन यह ठेकेदार माल को ट्रकों में भरता है और बाहर भेज देता है। इसलिए यदि सरकार उसको पाबन्द करके ग्लास फैक्ट्री वहां पर लगवा सकती है तो इस पर वह विचार करे। ग्लास फैक्ट्री वहाँ पर खुल

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

सकती है, इस पर भी विचार करें और जितने भी मजदूर हैं वह भी सरकार में विश्वास रखते हैं, उन्होने भी अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यहां भेजा है और उनके लिए सरकार कुछ करे ताकि उनका मानस स्वच्छ बना रहे।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

एक दो मिनट में ही समाप्त करता हूं।

राज्य परिवहन निगम की बसों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने इस बार नेशनलाइजेशन 25 परसेन्ट कर देने वाली बात कही है तो उनके लिए धन्यवाद लेकिन निगम की बसों की जो व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है। एक बार मैं एक बस में गया तो शिवदासपुरा के पास एक टायर फट गया और ड्राइवर को मालूम है कि टायर फट गया लेकिन फिर भी वह चलाये जा रहा है क्योंकि वह जानता है कि दूसरा टायर और उसके साथ है। वह और आगे चलता है और चाकसू के पास दोनों टायर फट जाते हैं। वहां पर पैसेन्जर पूछते हैं कि क्या हुआ उसने कहा कि टायर फट गया। उसके बाद में वह आगे बस नहीं ले गया क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है। बस उसने निवाई के पास खड़ी कर दी। पूछने पर ड्राइवर कहने लगा कि पाना नहीं है। एक बार एक गाड़ी में और बैठा तो रास्ते में ही गाड़ी खड़ी हो गई। ड्राइवर कहने लगा कि डीजल नहीं है। समझ में नहीं आता कि यह व्यवस्था कहां तक चलेगी। एक तरफ तो आप नेशनेलाइजेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अव्यवस्थायें हो रही हैं। ए. टी. आई. आता है और कन्डक्टर 10 रुपये उसे देकर अपना काम करता है ड्राइवर का फर्ज है कि गाड़ी खराब हो जाए तो साथ में सारी चीजें रखे और पैसेन्जर का ध्यान रखे। एक दफा मैं दिल्ली से चला तो मैंने देखा कि इन्स्पेक्टर भी वहीं पर बैठा था तो मैंने पूछा कि कितना रुपया कमाया तो कहा कि 200 रुपये कमाये। इस प्रकार की यह व्यवस्था है इसमें सुधार करना चाहिए। रास्ते में पैसेन्जर खड़े रहते हैं और उनको कोई नहीं उठाता है। जब पैसेन्जर को खड़ा देखते हैं तो और जोर से एक्सीलेटर को दबाते हैं और धुंआ छोड़ते हैं, धूल उड़ती है और इससे दस मिनट तक पैसेन्जर खड़ा परेशान रहता है और उसको होश नहीं आता इस प्रकार से उनको चेतावनी दी जाय कि जहां कहीं पैसेन्जर हों उनको उठाया जाय। प्राईवेट बसों में ऐसा नहीं होता है। वहां पर उनका सेल्फ इंटरैस्ट रहता है, उनका पर्सनल बेनिफिट होता है। वे जहां कहीं सवारियां मिलती हैं उनको लेते है और अगर नहीं भी लेते हैं तो भी हाथ से इशारा करते हैं। इस प्रकार की सारी की सारी व्यवस्था हम भी कर सकते हैं।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, भूमि के आवंटन का सवाल है। हम यह मानते हैं कि हमने नौ लाख या साढ़े नौ लाख लोगों को भूमि दी है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे देश में अस्सी प्रतिशत किसान हैं तो इस प्रकार हमने कितने आदमियों को भूमि दी है, कितने लोगों को जमीन मिली है। इसके अलावा जिनको जमीनें मिली हैं उनके भी हजारों तरह के विवाद हैं। कहीं पट्टे का चक्कर है तो कहीं पेनल्टी का चक्कर है, कहीं कमाण्ड एरिया

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

और अनकमाण्ड एरिया का चक्कर है, कहीं चरागाह का चक्कर है तो कहीं जंगलात का चक्कर है। इस प्रकार हजारों तरह के चक्कर किसान पर हैं। जिनको जमीनें मिली हैं उनको कचेरियों में जाकर खड़ा होना पड़ता है। आज आपको सबसे ज्यादा कचेरियों में किसान खड़े मिलेंगे। इस बारे में आपको निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए।

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में आगे के समय में क्या करना है और आप क्या करने जा रहे हैं उसका विवरण दिया है उससे हमें काफी सन्तोष है और जो माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य।

(किसी भी माननीय सदस्य के बोलने के लिए खड़े नहीं होने पर)

सदन की कार्यवाही दिनांक 11 मार्च, 1974 को प्रातः 11–00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 12.32 बजे सोमवार दिनांक 11 मार्च, 1974 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 7 मार्च, 1974)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	अन्तिम से 7	सत्र	सत्र
1	,, 3	बड़ा	बढ़ा
2	,, 1	सदस्य	सभापति
3	शीर्ष	विधाई	विधायी
	ऊपर से 2	विध्यक	विधेयक
	अन्तिम से 11	छगाणी	छंगाणी
6	ऊपर से 3	पोइन्ट	पाइन्ट
	,, 18	में	मैं
19	अन्तिम से 8	उ के	उनके
	,, 6	आ	और
	,, 4	ेर	और
	,, 3	तौड ोड	तोड़फोड़
20	ऊपर से 13	इ की	इनकी
	अन्तिम से 15	संहंगाई	मंहगाई
	,, 2	कपडो	—
22	ऊपर से 11	पढ़	पड़
31	अन्तिम से 1	पुरना	पुराना
33	अन्तिम से 15	लीगो	लोगों
	,, 12	वह	वे
35	,, 6	अभा	अभी
37	ऊपर से 1	केजरीमल	केसरीमल
45	,, 15	जि से	जिससे
47	,, 20	में	मैं
49	अन्तिम से 4	की	का
50	ऊपर से 6	म ी	मंत्री
53	,, 7	च हे	चाहे
	,, 10	पिछढे	पिछड़े
54	अन्तिम से 16	यह	वह
55	ऊपर से 2	दया	दिया

Page No 61

(61)

1	2		3	4
59	ऊपर से	9	एजेण्ड	एजेन्ट
60	अन्तिम से	10	उटावेंगे	उठावेंगे
61	ऊपर से	13	काग्रेश	कांग्रेस
	अन्तिम से	14	धिरादरी	विरादरी
61	अन्तिम से	2	डीक	ठीक
62	ऊपर से	1	खु	खुश
	,,	8	म्पत्ति	सम्पत्ति
	अन्तिम से	14	विवेच I	विवेचना
63	ऊपर से	2	वोट	वोटरों
66	,,	15	थे	था
102	,,	16		
	,,	18		
109	अन्तिम से	12	देख I	देखना
